सुबह सवेरे

A Daily News Magazine
भोपाल
बुधवार, 19 अगस्त, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 347, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

चीन को नेपाल में तिब्बत पर एक सेमीनार तक मंजूर नहीं

ऋषि गुप्ता

विदेशी मिशन किसी मेज़बान देश की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह की चर्चा हो सकती है, उसे प्रभावित करने में कितनी बार दिलचस्पी लेते हैं? बहुत कम, लेकिन ऐसा होता है। इस बार नेपाल में ऐसा हुआ।

बुद्ध के जन्मस्थान और बौद्ध दर्शन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में, नेपाल की काठमांडू यूनिवर्सिटी को 23 से 29 अगस्त तक तिब्बती अध्ययन पर एक हफ्ते की कॉन्फ्रेंस की सह-मेजबानी करनी थी। कॉन्फ्रेंस से तीन हफ्ते पहले, नेपाल के सरकारी अधिकारियों ने आयोजकों को मौखिक रूप से निर्देश दिया कि वे 'इस आयोजन को आगे न बढ़ाएं।' बाद में मीडिया ने बताया कि कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है और फिर इसकी पुष्टि हुई कि इसे ऑनलाइन कर दिया गया। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर तिब्बतन स्टडीज (IATS) और काठमांडू यूनिवर्सिटी ने मिलकर इसका आयोजन किया था। IATS तिब्बती अध्ययन की एक प्रमुख संस्था है, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी और जिसका घोषित उद्देश्य 'इतिहास, धर्म, भाषा-विज्ञान और कला जैसी सभी शाखाओं के नजरिए से तिब्बत का अध्ययन करना' है। यह इस संस्था का 17वां सम्मेलन था।

मीडिया रिपोर्टें इस फैसले की एक मुख्य वजह की तरफ साफ इशारा करती हैं। वह है चीन। खबरों के मुताबिक, चीनी मिशन ने काठमांडू में होने वाली IATS कॉन्फ्रेंस को लेकर नेपाल के अधिकारियों के सामने 'चिंता' जताई थी। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से, जिसमें ताइवान भी शामिल है, आने वाले कुछ विद्वानों ने इस फैसले पर अपनी निराशा जाहिर की है। ताइवान से आने वाले एक प्रतिभागी ने आयोजकों द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट साझा किया। उसमें लिखा था, 'नेपाल सरकार ने काठमांडू यूनिवर्सिटी को IATS के 17वें सेमिनार के आयोजन को आगे न बढ़ाने का निर्देश दिया है।' इस प्रतिभागी ने आखिरी समय में हुए इस बदलाव पर निराशा जताई।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इस घटना को विस्तार से कवर किया है और नेपाल में इस तरह के कदम पर सवाल उठाए हैं। प्रतिभागियों ने भी इसकी निंदा की है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने एक बौद्धिक रूप से दिलचस्प अनुभव के लिए एक महंगी यात्रा करने का फैसला किया था। लेकिन यह समझने के लिए कि यह चीन की नेपाल नीति को किस तरह दिखाता है, पूरी तस्वीर को समझना ज़रूरी है।

यह चीन की तरफ से नेपाल में तिब्बत से जुड़े मामलों को लेकर किया गया पहला विरोध नहीं है, बल्कि ऐसे कई विरोधों में से एक है, और काठमांडू ने दबाव में आकर कदम उठाया है। चीन के नेपाल के साथ राजनयिक संबंधों के सात दशकों के दौरान, तिब्बत बीजिंग के लिए काठमांडू में एक मुख्य सुरक्षा चिंता बना रहा है। 1960 के दशक में, कम्युनिस्ट चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद, हजारों तिब्बती पड़ोसी देश नेपाल भाग गए और वहां शरण लेकर रहने लगे, जबकि ज्यादातर लोग भारत चले गए ताकि तिब्बत की निर्वासित सरकार के साथ रह सकें।

तिब्बत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव तिब्बत से नेपाल की इस बड़े पैमाने की पलायन की एक बड़ी वजह था। दो दशकों तक यह आवाजाही बिना बड़ी रुकावट के चलती रही, लेकिन 1990 के दशक में राजशाही और सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा। 1990 के दशक में बीजिंग के काठमांडू पर दबाव के बाद हिमालय पार करके नेपाल पहुंचने वाले शरणार्थियों की संख्या कम हो गई। इस बीच, 2008 में माओवादियों के नेतृत्व में पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार बनने के बाद, नेपाल में तिब्बतियों की आवाजाही भी ज्यादा नियंत्रित हो गई। 2008 वही साल था जब बीजिंग ओलंपिक के सामने ल्हासा में एक बड़ा विद्रोह हुआ था। नेपाल में तिब्बती विद्रोह के लिए किसी भी तरह के समर्थन को चीनी हितों के लिए खतरा पैदा करने वाला सुरक्षा मामला माना जाने लगा।

2008 की अपनी रिपोर्ट में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया था कि चीन के कथित दबाव के बाद नेपाल में 8,350 तिब्बतियों को गिरफ्तार किया गया था। जबकि ज्यादातर तिब्बती शरणार्थी अमेरिका, कनाडा और दूसरे देशों में चले गए, नेपाल में बचे हुए लोग स्थानीय समुदायों में घुल-मिल गए हैं, फिर भी चीन का डर बना हुआ है। अगर वे एकजुट नहीं भी हैं, तब भी 'फ्री तिब्बत' की सोच नेपाल के तिब्बती समुदाय के बीच भावनात्मक महत्व रखती है, और अक्सर युवाओं में इसे लेकर ज्यादा जोश दिखाई देता है।

इसी समय, तिब्बती अध्ययन पर सेमिनार जैसे कार्यक्रमों को खतरा माना जाना हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इसमें दुनिया भर के उन देशों से प्रतिभागी आए थे जहां बोलने की आज़ादी है, और यह किसी भी तिब्बती मुद्दे के समर्थन की जगह भी बन सकता था। यह याद रखना भी ज़रूरी है कि चीन के नेपाल के साथ सात दशकों के राजनयिक इतिहास में हर संयुक्त बयान, संधि और समझौते में बीजिंग की ओर से काठमांडू से यह मांग शामिल रही है कि वह 'ताइवान, तिब्बत से जुड़े मामलों और चीन के मूल हितों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर अपने मजबूत समर्थन' को दोहराए।

2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान जारी संयुक्त बयान में कहा गया था, 'तिब्बत के मामले चीन के आंतरिक मामले हैं, और अपनी धरती पर किसी भी चीन-विरोधी गतिविधि को होने नहीं देने का संकल्प है। 'इसलिए चीन नेपाल में तिब्बत से जुड़ी गतिविधियों पर करीबी नजर रखता है। इसकी वजह यह है कि राजनीतिक आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का सीमित रूप से भी नेपाल से तिब्बत तक फैलना तिब्बत को प्रभावित कर सकता है और चीन की घरेलू स्थिरता के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

इसके अलावा, जेन ज़ी के नेतृत्व में बनी नई सरकार के साथ बीजिंग में यह डर बढ़ रहा है कि तिब्बत से जुड़ी गतिविधियां ज्यादा प्रमुख हो सकती हैं, क्योंकि जेन ज़ी नेतृत्व ज्यादा स्वतंत्र और कम अनुमान लगाने योग्य है।

1955 में नेपाल और चीन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से बीजिंग ने यह साफ रखा है कि वह नेपाल से क्या चाहता है – तिब्बत, ताइवान या वन-चाइना पॉलिसी। लेकिन चुनौती काठमांडू के साथ रही है, जिसने लंबे समय तक चीन की एक लंबी अवधि की नीति को समझने पर ध्यान नहीं दिया और बीजिंग की संवेदनशीलताओं के मुताबिक चलता रहा। अगर तिब्बत में चीन की घरेलू स्थिरता के लिए नेपाल इतना महत्वपूर्ण है, तो काठमांडू यह क्यों नहीं समझता कि चीन के साथ बातचीत में तिब्बत उसके लिए सबसे बड़ा दबाव बनाने वाला साधन और सौदेबाजी का मुद्दा हो सकता है? एकतरफा तरीके की नेपाल को अक्सर बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का हलफनामा

गैरकानूनी था 'सीजेपी' का संसद मार्च

● कहा- हिस्ट्रीशीटर शामिल हुए, बैरिकेड भी तोड़े ● पुलिस बोली- हमने ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैरकानूनी था। इसकी परमिशन नहीं थी। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में कई हिस्ट्रीशीटर भी आ गए थे। पुलिस ने बताया कि संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस से मारपीट की, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा ने हलफनामा

दाखिल कर ये जानकारी दी। इसे पुलिस ज्यादती की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाओं के जवाब के तौर पर पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाई लेवल कमेटी बनाएगा।

पुलिस का हलफनामा बताई हकीकत

20 जुलाई को जंतर–मंतर के आसपास 30 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौजूद थे। करीब 3 किलोमीटर के इलाके में फैली इस भीड़ को संभालने के लिए लगभग 5 हजार पुलिसकर्मी तैनात थे। झड़प में 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और करीब 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए। याचिकाओं में चुनिंदा फोटो, अधूरे वीडियो और अपुष्ट मीडिया रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया। इनमें पुलिस की कार्रवाई का पूरा संदर्भ नहीं दिखता। वीडियो में ऐसी लाठी की सिर्फ एक घटना दिखती है।

सुप्रीम आदेश, हाईलेवल कमेटी करेगी जांच

सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी के नेतृत्व वाले छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए हाईलेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, पूर्व डीआईजी, पूर्व सीबीआई प्रमुख समेत अन्य सदस्य होंगे। कोर्ट बुधवार को कमेटी के गठन का औपचारिक आदेश जारी करेगा। इससे पहले याचिकाकर्ताओं और अन्य पक्षों से चर्चा होगी।

भिंड में ट्रक से टकराई पिकअप, 8 की मौत

● 23 घायल, ग्वालियर से यूपी लौट रहे थे; हाईवे पर गायों को बचाने में हुआ हादसा

भिंड (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के भिंड में नेशनल हाईवे-719 पर गोहद इलाके में सोमवार देर रात करीब 1 बजे तेज रफ्तार पिकअप सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इससे 8 लोगों की मौत हो गई। 23 घायल हैं। इनमें ट्रक ड्राइवर भी शामिल है। घायल नंदलाल बताया कि पिकअप में कुल 29 मजदूर सवार थे। सभी अलग-अलग गांव के थे। ये लोग ग्वालियर से धान की रोपाई का काम पूरा कर घर लौट रहे थे। पहले चार मजदूरों की मौत और 25 के घायल होने की जानकारी आई थी। हादसे के बाद गोहद चौराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

मुझे देखकर जो जला जा रहा था,
सुना है वो मेरी ग़ज़ल गा रहा था।
जलाई थी जिसने वो कल रात बस्ती,
सुबह से वो इम्दाद पहुँचा रहा था।
था चलना सिखाया पकड़ उंगली जिसने,
उसे आज पागल वो बतला रहा था।
छुरा जिसने घोंपा मेरी पीठ पर कल,
वही आज घावों को सहला रहा था।
सुबह धर्म जिसने अहिंसा बताया,
वही शाम को मछलियां खा रहा था।
जो तुमको लगा शेर सबसे ही अच्छा,
वही शेर मुझसे न बन पा रहा था।

- विश्वनाथ तिवारी 'विश्व'

रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त

आज मैहर से खाते में 1750 रुपए ट्रांसफर करेंगे सीएम; 1.25 करोड़ महिलाओं को लाभ

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बुधवार 19 अगस्त को मैहर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 13 हजार से अधिक पात्र बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से कुल 2,148 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मैहर जिले में 256 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में इस बार रक्षाबंधन पर बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। हर महीने मिलने वाली 1500 रुपए की किस्त के साथ यह राशि जुड़ने से 19 अगस्त को लाड़ली बहनों के खातों में कुल 1750 रुपए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मैहर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 35 हजार महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त के रूप में 1,500 प्रति हितग्राही कुल 1,835.46 करोड़ रूपये से अधिक और रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर 250 प्रति हितग्राही कुल 312.83 करोड़ रूपये से अधिक की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में हुए कई अहम फैसले

लाड़ली लक्ष्मी-बहनों को मिलते रहेंगे रुपए, 5 साल की मंजूरी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और जीवनदायिनी माँ नर्मदा के संरक्षण, पुनर्जीवन तथा दीर्घकालीन सतत प्रबंधन के लिए 'निर्मल एवं अविरल माँ नर्मदा मिशन (नमन मिशन)' के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसी तरह मंत्रि-परिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और वैज्ञानिक क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 734 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। पिछले बीस वर्षों में प्रदेश में वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन द्वारा बजट में लगभग 150 गुना वृद्धि की गयी है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और तकनीकी प्रगति को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं के आगामी वर्षों में निर्बाध संचालन के लिए लगभग 1 लाख 46

हजार करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके साथ ही, महिला कल्याण को प्राथमिकता देते हुए 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' के लिए 1,14,365 करोड़ रुपये, 'मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना' के लिए 16,326.47 करोड़ रुपये और 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के लिए 2,137.65 करोड़ रुपये की वित्तीय निरंतरता को मंजूरी दी गई है।

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं अधोसंरचना विस्तार के लिए 11 हजार 835.35 करोड़ रुपये, कृषि शिक्षा व अनुसंधान के लिए 870 करोड़ 16 लाख रुपये तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।

निर्मल एवं अविरल माँ नर्मदा मिशन (नमन मिशन) के गठन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश को जीवनदायिनी नर्मदा नदी के संरक्षण, पुनर्जीवन और दीर्घकालीन सतत प्रबंधन के लिए निर्मल एवं अविरल माँ नर्मदा मिशन (नमन मिशन) के गठन की स्वीकृति दी है।

नमन मिशन की प्रबंधन संरचना

नमन मिशन को म.प्र. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

734 करोड़ रुपए है साइंस-टेक्नोलॉजी का बजट

राज्य सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों के लिए 492 करोड़ से अधिक की योजनाएं संचालित करेगी। राज्य सरकार का साइंस-टेक्नोलॉजी के लिए बजट 734 करोड़ रुपये है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी रिपोर्ट में चंपत-अनिल का नाम नहीं

बाकी 8 आरोपी पहले ही जेल में, एसआईटी ने फाइनल जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए यूपी सरकार की बनाई एसआईटी ने सोमवार रात फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक, इसमें ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। बाकी 8 आरोपी पहले ही जेल में हैं। यूपी के गृह विभाग ने रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास को

सौंपी है। इसे राम मंदिर ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली बैठक में रखा जाएगा। ट्रस्ट ने ही उत्तर प्रदेश सरकार से चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच का अनुरोध किया था। यूपी सरकार ने 13 जून को लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एसआईटी बनाई थी। आईजी रेंज किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार इसके सदस्य थे। एसआईटी ने 23 जून को प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की कमान आईजी को सौंपने के आदेश दिए।

23 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, 2 दिन बाद 8 की गिरफ्तारी

चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया। यूपी सरकार की एसआईटी ने 23 जून को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (गृह) संजय प्रसाद को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। 25 जून को ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 को नामजद किया गया। हालांकि, इसमें चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं थे। एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान में सभी फैजाबाद जेल में हैं। सभी पर चढ़ावा गिनती करते वक्त नोटों और गहनों की चोरी का आरोप है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 19 अगस्त 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

10 ई-बसें और चलीं, बैरागढ़, कोलार-बावड़ियाकलां में बेहतर होगी कनेक्टिविटी; सभी एमपी नगर से गुजरेंगी

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शामिल ई-बसों की मंगलवार से संख्या बढ़ गई है। 10 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर और उतरी। इसके बाद इनकी संख्या 20 हो गई है। बैरागढ़, कोलार रोड, बावड़ियाकलां तक बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। सभी बसें एमपी नगर से होकर जरूर गुजरेंगी। ऐसे में नौकरीपेशा और पढ़ाई करने वालों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

वर्तमान में ई-बसों को ऐसे 3 रूट पर चलाया जा रहा है, जो शहर के बड़े हिस्से को कवर कर लेती हैं। इनमें बैरागढ़, कोलार रोड, एमपी नगर, न्यू मार्केट, कोलार रोड, बावड़ियाकलां, सलैया, रोहित नगर, अशोका गार्डन, सुभाषनगर, कोहेफिजा, पीर गेट जैसे बड़े इलाके भी शामिल हैं। इनका न्यूनतम किराया 6 से 7 रुपए, जबकि अधिकतम 40 रुपए है।

हर रोज 12 हजार यात्रियों को होगा फायदा- राजधानी में ई-बसों का बेड़ा मंगलवार को दोगुना हो जाएगा। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (बीसीएलएल) कुल 20 ई-बसें चलाएगा। अब तक दौड़ रही 10 बसों में एक दिन में औसत 4500 यात्री सफर कर रहे थे। इनमें स्कूल-कॉलेज की छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की संख्या अधिक है। मंगलवार से 10 बसें और चलेंगी। इससे 10 से 12 हजार यात्री रोज सफर कर सकेंगे।

इन 3 रूटों पर दौड़ेंगी ई-बसें- बी35- चिरायु अस्पताल, बैरागढ़ से आकृति ईको सिटी, सलैया चिरायु अस्पताल, बैरागढ़ मार्केट, लालघाटी, कलेक्ट्रेट, हमीदिया हॉस्पिटल, रॉयल मार्केट, पीर गेट, कमला पार्क, पॉलिटेक्निक चौराहा, रंगमहल चौराहा, रोशनपुरा, नानके पेट्रोल पंप, लिंक रोड नंबर-1, प्रकाश तरण पुष्कर, रेडक्रॉस अस्पताल, बोर्ड ऑफिस, एमपी नगर मेट्रो स्टेशन, भाजपा कार्यालय, विट्ठन मार्केट, 1100 क्वार्टर, 12 नंबर बस स्टॉप, ईश्वर नगर, तिलक नगर, रोहित नगर, बावड़िया चौराहा, आकृति ईको सिटी होते हुए सलैया तक।

बी36- कोच फैक्ट्री से कोलार रोड तक- द्वारका नगर, कोच फैक्ट्री भोपाल रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नं-1, पुष्पा नगर, अशोका गार्डन, प्रभात पेट्रोल पंपचौराहा, ओल्ड सुभाष नगर, शांति निकेतन, चेतक ब्रिज तिराहा, बोर्ड ऑफिस चौराहा मेट्रो स्टेशन, एमपी नगर मेट्रो स्टेशन, भाजपा कार्यालय, सुभाष स्कूल, विट्ठन मार्केट, 1100 क्वार्टर, मनीषा मार्केट, बंसल अस्पताल, चूनाभट्टी चौराहा, मंदाकिनी चौराहा, नयापुरा, ललिता नगर, गेहूंखेड़ा, बैरागढ़ चिचली होते हुए कोलार रोड तक।

बी37- बैरागढ़ ई-बस डिपो से आईएसबीटी- बैरागढ़ ई बस डिपो से बैरागढ़ मार्केट, लालघाटी, कलेक्ट्रेट, हमीदिया हॉस्पिटल, रॉयल मार्केट, एलबीएस हॉस्पिटल, शाहजहांनाबाद, भोपाल टॉकीज, नादरा बस स्टैंड, रेलवे प्लेटफॉर्म नं-6 भारत टॉकीज, लेडी हॉस्पिटल, जहांगीराबाद, पीएचक्यू, मालवीय नगर, मिंटो हॉल, बिड़ला मंदिर, वल्लभ भवन, विंध्याचल, जिला न्यायालय, डीबी मॉल, चेतक ब्रिज होते हुए आईएसबीटी तक।

संक्षिप्त समाचार

मैं,जब विधायक बना था तब अमित शाह बच्चे थे

- मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- वह हमें देशभक्ति न सिखाएं

पणजी (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि जब मैं पहली बार विधायक बना था, तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति

सिखा रहे हैं। उन्होंने यह बात दक्षिण गोवा में एक जनसभा में कही। वहीं, खड़गे ने कहा, 'बीजेपी धर्म विरोधी हैं, क्योंकि जब मैंने 8 अगस्त को उत्तराखंड में हल्द्वानी के रामलीला मैदान पर सभा की थी तो 2 दिन बाद मंच का शुद्धिकरण किया गया। ऐसा लगा जैसे मुझे अछूत माना गया हो। क्या लोकतंत्र ऐसे चलता है। देश में दलितों के लिए क्या कोई जगह नहीं है। दरअसल, शाह ने 16 अगस्त को आरोप लगाया था- 'कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। बीच में ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को गान को रोकने को कहा था।'

अमित मालवीय जहां चूके बीजेपी का वहीं फोकस!

- आईटी सेल के नए प्रमुख दीपक महस्के का बड़ा प्लान

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमित मालवीय की जगह बीजेपी आईटी सेल की नई जिम्मेदारी संभालने वाले दीपक महस्के ने कहा है कि

उनकी प्राथमिकता जेन जी है। नई पीढ़ी में पार्टी की पैठ बढ़ाने के लिए वह इंस्टाग्राम पर फोकस कर रहे हैं। दीपक महस्के ने इंस्टाग्राम और जेन जी में पैठ बनाने को कोशिशों को प्राथमिकता बताया है। कहा कि पार्टी अपनी डिजिटल मौजूदगी को मजबूत करने और युवा वोटरों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। **पार्टी का मुख्य फोकस इंस्टाग्राम-** नई जिम्मेदारी संभालने के बाद म्हास्के ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी का मुख्य फोकस इंस्टाग्राम पर होगा।

जंतर-मंतर और झारखंड के बाद पटना में संग्राम

छात्रों का महाधरना,लालू यादव ने लोकभवन मार्च का किया आह्वान

पटना (एजेंसी)। बिहार में भी छात्र आंदोलन तेज हो गया है। टीआरई-4 की मांग को लेकर पटना में महाधरना का आयोजन

किया गया। वहीं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से 19 अगस्त को लोकभवन मार्च का आह्वान किया है। टीआरई-4 विज्ञापन और एकल परीक्षा की मांग को लेकर मंगलवार को पटना में छात्रों का महाधरना शुरू हुआ। इस धरना- प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र बैठे हैं।

एदल सिंह कंसाना ने प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनी जनसमस्याएं

जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री एदल सिंह कंसाना ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से आत्मीय मुलाकात कर उनकी जनसमस्याओं एवं सुझावों को सुना। उन्होंने कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न विषयों पर संबंधित अधिकारियों से तत्काल चर्चा कर समाधान कराया। जिन प्रकरणों में विस्तृत प्रक्रिया अपेक्षित है, उन्हें संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई एवं शीघ्र निराकरण के लिए भेजा गया।

मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री एदल सिंह कंसाना ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी ओर से प्राप्त जनसमस्याओं का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त जनसमस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान भाजपा सरकार एवं संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

योगी का ऐलान, पीआरओ जवानों का भत्ता 600 करेंगे

गोरखपुर में कैशलैस योजना शुरू की, 5 लाख तक इलाज फ्री होगा

गोरखपुर (एजेंसी)। सीएम योगी ने मंगलवार को गोरखपुर में पीआरडी (प्रांतीय रक्षक दल) जवानों के लिए 'मुख्यमंत्री पीआरडी परिवार कल्याण योजना' का शुभारंभ किया। इसमें पीआरडी जवान के परिवार का 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होगा। योगी ने ऐलान किया कि जल्द ही PRD जवानों का भत्ता रोजाना 600 किया जाएगा। इसकी तैयारी की जा चुकी है। अभी पीआरडी जवानों को 500 रुपए मिलते हैं। प्रदेश में 31 पीआरडी जवान रजिस्टर्ड हैं। इसमें 2 हजार से ज्यादा महिलाएं हैं। सीएम ने पीआरडी जवानों के वर्दी भत्ते के 3000 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर किए। इससे पहले लखनऊ में बनने वाले पीआरडी भवन का शिलान्यास किया। 1948 में गठित प्रांतीय रक्षक दल के जवान (स्वयंसेवक) पुलिस के काम में मदद करते हैं। योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में योगी ने कहा- पीआरडी जवानों को सुविधा मिली है तो उन्हें और बेहतर ढंग से काम करना होगा। हम सब भारतवासियों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। वह है 'देश प्रथम'। जो बांटने का काम करते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। पीआरडी जवानों का भत्ता 2019 तक 250 रुपए था। 2019 में इसे बढ़ाकर 375 किया। 2022 में 395 रुपए किया। फिर 500 किया। योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा- पिछली सरकारें अपनी पीढ़ियों के लिए पैसा जमा करती थीं। प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे। ये सोचते हैं कि कोई दिक्कत होगी तो वहां भाग जाएंगे। अमेरिका-ईरान युद्ध में मिसाइल वहीं गिर रही थी, जहां पैसा जमा था। युद्ध वहां हो रहा था, परेशान नेता थे। अब दंगाई और माफिया हमेशा के लिए रसातल में चले गए हैं। योगी ने कहा- आज यूपी बीमारू नहीं रहा। विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमने यहां की अर्थव्यवस्था को तीन गुना कर दिया है। पहले 43 हजार प्रति व्यक्ति आय थी, आज 1 लाख 20 हजार हो गई है। आज बजट 9 लाख 70 हजार करोड़ पहुंच गया है। वे लुटवाते थे, लूटते थे। प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे। सीएम ने कहा- आरोप-प्रत्यारोप वही करते हैं जो कुछ कर नहीं पाते। उन्हें लगता है कि हम कर नहीं सके, इन्होंने कैसे कर दिया। यही उनकी समस्या है।

हर भारतीय वोटर के पास फोटो आईडी, अमरीका में नहीं

ट्रंप बोले-अमेरिका में भी हो भारत जैसा चुनावी सिस्टम

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को भारत की चुनाव व्यवस्था की जमकर तारीफ की और कहाकि ऐसी व्यवस्था अमरीका में भी होनी चाहिए। यहां के चुनावों का हवाला देते हुए 'सेव अमेरिका एक्ट' को पास कराने की अपील की है। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में लिखा- इस महीने की शुरुआत में, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था कि अमेरिका में वैध फोटो आईडी के बिना चुनाव कैसे हो सकते हैं। ट्रम्प ने आगे कहा- हमें अब सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा। ट्रम्प ने अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को और सख्त बनाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि इससे अमेरिकी चुनावों की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ेगी। सेव अमेरिका एक्ट अमेरिका में मतदाता पंजीकरण और मतदान से जुड़े नियमों को और सख्त करेगा।

हर छात्र के साथ खड़े हैं, बदलकर रहेंगे वसूली तंत्र!

- झारखंड के छात्र मुद्दे पर राहुल गांधी का बड़ा बयान

रांची (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने झारखंड में छात्र आंदोलन के मुद्दे पर बड़ी बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी, और छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की , यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि वो देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं। वो इस वसूली तंत्र को जड़ से बदलकर रहेंगे, ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत का पूरा फल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक मिले।

फांसी की जगह दूसरा तरीका अपनाने की अर्जी हुई खारिज

सुप्रीम फैसला, सजा के दूसरे विकल्पों की जांच का रास्ता खुला

नई दिल्ली (एजेंसी)। मौत की सजा सुनाए जाने के बाद किसी कैदी को किस तरीके से मौत दी जाए, इस पर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। क्या फांसी ही सबसे सही तरीका है या ऐसा कोई दूसरा तरीका हो सकता है, जिसमें दर्द और तकलीफ कम हो और आखिरी समय में कैदी की गरिमा भी बनी रहे। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने फांसी को मौत की सजा देने का तरीका खत्म करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया कि केंद्र सरकार चाहे तो एक्सपर्ट्स की मदद से दूसरे तरीकों की जांच कर सकती है। अगर भविष्य में मजबूत वैज्ञानिक या मेडिकल सबूत सामने आते हैं, तो इस मुद्दे पर फिर संवैधानिक जांच भी हो सकती है।

कम दर्द देने वाले तरीके अपनाए जाएं

वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा ने 2017 में यह याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि फांसी की प्रक्रिया में 40 मिनट से ज्यादा लग सकते हैं, जबकि गोली मारने में कुछ मिनट और जहरीले इंजेक्शन में करीब 5 मिनट लगने का दावा किया गया। याचिका में बीएनएस की धारा 354(5) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। इसी धारा के तहत मौत की सजा पाए दोषी को गर्दन से लटकाया जाता है।

बीजेपी ने दी बड़ी जिम्मेदारी, जगदीश पटेल सह प्रभारी होंगे

बिहार जिताने वाले तावड़े को यूपी का मिला प्रभार

- सतीश पूनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए राज्य प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए। बिहार चुनाव जिताने वाले विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी नियुक्त किया है। पंजाब की जिम्मेदारी सतीश पूनिया को दी गई है। गुजरात का जिम्मा तरुण चुग को सौंपा गया है। इन तीनों राज्यों में अगले साल चुनाव हैं। भाजपा अध्यक्ष ने एक दिन पहले अपनी नई टीम का ऐलान किया था। इसमें 65 पदाधिकारियों की घोषणा की थी।

तीनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव

2027 में उत्तर प्रदेश और गुजरात में बीजेपी के सामने सत्ता बरकरार रखने, जबकि पंजाब में अपना आधार मजबूत करने की चुनौती होगी। ऐसे में इन तीन राज्यों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति को बीजेपी की शुरुआती चुनावी तैयारियों और संगठन को मजबूत करने की कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश- 403 विधानसभा सीटों वाले राज्य में अगले साल फरवरी-मार्च में चुनाव होने की संभावना है। यहां फिलहाल बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में झटका लगा था। ऐसे में 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए राज्य में सत्ता बरकरार रखने के साथ 2024 के लोकसभा प्रदर्शन के बाद अपनी पकड़ मजबूत करने की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। पंजाब- 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में एएपी ने 92 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। 2027 में बीजेपी भी सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में पंजाब में मुकाबला बीजेपी के लिए संगठन विस्तार और सत्ता में मौजूद एएपी के सामने अपनी स्थिति मजबूत करने की चुनौती वाला होगा। गुजरात- 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में दिसंबर 2027 तक चुनाव होने की संभावना है। यहां बीजेपी की सरकार है। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया था। पार्टी के लिए 2027 में इस प्रदर्शन को दोहराना बड़ी चुनौती होगी।

बच्चों की कल्पनाशीलता ने दिया प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश

- हरा-भरा इंदौर का संकल्प लेकर किया गया पौधरोपण

इंदौर। शहर के गांधी हॉल में मंगलवार को नन्हें बच्चों ने पेंटिंग और फेंसी ड्रेस्स प्रतियोगिता के साथ स्लोगन लेखन के माध्यम से प्रकृति, पर्यावरण, जल और जंगल के संरक्षण का अभूतपूर्व संदेश दिया। नन्हें बालक-बालिकाओं की तूलिका ने रंगों का अद्भुत संसार रच दिया। यह आयोजन मां अहिल्या सेवा संस्था मध्यप्रदेश एवं श्रीजी नारी शक्ति एवं शिक्षा विकास समिति की ओर से प्रकृति सहेजो पर्यावरण बचाओ अभियान की थीम पर आयोजित किया गया था। मां अहिल्या सेवा संस्था मध्यप्रदेश की डायरेक्टर डॉ. आरती मेहरा ने बताया कि सावन और राखी और हरियाली महोत्सव के मद्देनजर गांधी हॉल में विभिन्न उत्पादों के स्टाल अतिथियों और नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। मां अहिल्या सेवा संस्था की उपाध्यक्ष रश्मि बाकीवाला ने बताया कि यह प्रोग्राम मुख्य अतिथि शंकर लालवानी के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर महिलाओं और युवतियों ने विभिन्न व्यंजनों के स्टाल भी लगाए। अपरान्ह तीन बजे पेड़ लगाओ स्वच्छ सुंदर और स्वस्थ हरा भरा इंदौर बनाओ अभियान के तहत बच्चों से दो-दो पौधों का रोपण करवाया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों दो हाथ और दो पेड़ लगाने और उनका संरक्षण करने का और उन्हें पौधे से पेड़ बनाओ से अभियान से जोड़ना रहा। निशुल्क ड्राइंग, स्लोगन और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर अतिथियों ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी, विशेष अतिथि सीबी रॉकस्टार चिंतन बाकीवाला थे। मां अहिल्या सेवा संस्था की डायरेक्टर डॉ. आरती मेहरा, मां अहिल्या सेवा संस्था की उपाध्यक्ष रश्मि बाकीवाला और श्रीजी नारी शक्ति और विकास समिति की डायरेक्टर श्वेता विभोर जैन, सहसंयोजक एडवोकेट संजय मेहरा और विभोर जैन सहित बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे।

भोपाल में पहली बार 'जेन अल्फा प्रोटेस्ट'

रीजनल स्कूल के 300-400 छात्र सड़क पर उतरे, बोले- डीएमएस को केवी में मर्ज नहीं होने देंगे

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल में मंगलवार को पहली बार किसी शैक्षणिक संस्थान के मुद्दे पर 'जेन अल्फा प्रोटेस्ट' देखने को मिला। रीजनल स्कूल के करीब 300 से 400 छात्र-छात्राएं रीजनल स्कूल को केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) में मर्ज किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में सड़क पर उतर आए।

बच्चों के हाथों में 'सेव डीएमएस' समेत अलग-अलग पोस्टर थे। छात्रों ने रीजनल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. एसके गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर संविलयन का विरोध दर्ज कराया। साथ ही मांगें नहीं माने जाने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी।

मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने इसे राजधानी में हुआ प्रदेश का पहला 'जेन अल्फा प्रोटेस्ट' बताया। उन्होंने कहा कि इससे पहले विदिशा में बस किराए से जुड़े मुद्दे को लेकर गांव के बच्चों द्वारा जेन अल्फा प्रोटेस्ट किए जाने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन किसी शैक्षणिक संस्थान के मुद्दे को लेकर भोपाल में छात्रों का यह पहला ऐसा प्रदर्शन है।

सेव डीएमएस' के पोस्टर लेकर पहुंचे छात्र- प्रदर्शन के दौरान छात्र-छात्राओं के हाथों में 'सेव डीएमएस' लिखे पोस्टर नजर आए। डीएमएस यानी डेमोंस्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल को हिंदी में प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय कहा जाता है। छात्रों और

अभिभावकों का कहना है कि रीजनल स्कूल सामान्य स्कूल नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग और नवाचार के लिए इसकी अलग पहचान है।

विवेक त्रिपाठी के अनुसार एनसीईआरटी के अंतर्गत शिक्षा में नवाचार और शैक्षणिक प्रयोग के लिए चार शैक्षणिक प्रयोगशालाएं दिसंबर 1965 से प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय के नाम से भोपाल, अजमेर, मैसूर और भुवनेश्वर में संचालित होती रही हैं। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों को केंद्रीय विद्यालय संगठन में शामिल किए जाने की प्रक्रिया का ही छात्र विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन स्कूलों की मूल अवधारणा शिक्षा में नए प्रयोग और नवाचार करना है।

क्या है छात्रों की मांग?

छात्रों की मुख्य मांग है कि रीजनल स्कूल का केंद्रीय विद्यालय संगठन में संविलयन नहीं किया जाए। उनका कहना है कि स्कूल की अलग शैक्षणिक पहचान और प्रयोगात्मक स्वरूप को बनाए रखा जाए। प्रदर्शन के बाद छात्रों ने प्राचार्य प्रो. एसके गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं। ज्ञापन के जरिए संविलयन की प्रक्रिया को रोकने और मौजूदा स्वरूप को बनाए रखने की मांग की गई। छात्रों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

अभिभावकों को एडमिशन पॉलिसी बदलने की चिंता

प्रदर्शन में शामिल छात्रों के अभिभावकों को सबसे बड़ी चिंता केंद्रीय विद्यालय की प्रवेश नीति को लेकर है। अभिभावकों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश की प्राथमिकताएं अलग हैं। ऐसे में रीजनल स्कूल के मौजूदा छात्रों और भविष्य में सामान्य परिवारों के बच्चों के प्रवेश को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक छात्र के पिता ने बताया कि उन्हें संविलयन की जानकारी औपचारिक रूप से नहीं दी गई। कुछ अभिभावकों और स्कूल स्टाफ के माध्यम से यह जानकारी सामने आई, जिसके बाद अभिभावकों ने आपस में चर्चा शुरू की। उनका कहना है कि इतने बड़े निर्णय से पहले छात्रों और अभिभावकों से भी बात की जानी चाहिए थी।

सरकारी स्कूलों के मर्जर पर तत्काल रोक लगे

शिक्षकों के खाली पदों को तुरंत भरा जाए, छात्राएं पढ़ाई छोड़ने को हो रही हैं मजबूर : अजय सिंह

भोपाल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश में सरकारी स्कूलों की मर्जर प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर दूर-दराज के क्षेत्रों में किए गए सभी मर्जर आदेशों को निरस्त किया जाए। इसके साथ ही प्राथमिकता के आधार पर बजट आवंटित कर स्कूलों के जर्जर भवनों को सुधारा जाए और शिक्षकों के खाली पदों को तुरंत भरा जाए।

सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'एक परिसर, एक शाला' और संदीपनी स्कूल नीति के नाम पर सरकारी स्कूलों के अंधाधुंध मर्जर की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार मर्जर का बहाना बनाकर वास्तव में प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। सरकार की इस अदूरदर्शी नीति का सबसे घातक असर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब विद्यार्थियों विशेषकर छात्राओं की शिक्षा पर पड़ रहा है।

अजय सिंह ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग खुद के बनाए नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। स्कूलों के मर्जर के लिए दो किलोमीटर के दायरे का नियम है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पांच से दस किलोमीटर दूर स्थित स्कूलों को आपस में मर्ज किया जा रहा है। सागर, उज्जैन, सीहोर, सतना, रायसेन और विदिशा समेत पूरे प्रदेश से इसके खिलाफ लगातार विरोध की आवाजें उठ रही हैं। उज्जैन में तो सैकड़ों छात्राओं को मजबूरी में सड़क पर उतरकर इस गलत नीति का विरोध करना पड़ा है।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्कूलों की दूरी बढ़ने और बार-बार स्कूल बदले जाने के कारण छात्राओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा और परिवहन के साधनों के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा देने वाली भाजपा सरकार का यह कदम प्रदेश की बेटियों के भविष्य को अंधकार में धकेलने वाला है। सिंह ने शासन की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के पास सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों को ठीक करने, शिक्षकों की कमी को पूरा करने और पेयजल व शौचालयों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कार्ययोजना नहीं है। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सरकार स्कूलों को मर्ज कर उन पर ताला लगाने का आसान रास्ता चुन रही है।

पेंशन केंद्रीय व्यवस्था के अनुरूप पुनरीक्षित करने की मांग

भोपाल। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 1 जनवरी 2016 से पूर्व पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन को केंद्र की व्यवस्था के अनुरूप पुनरीक्षित करने की पुरजोर मांग करते हुए मुख्य सचिव एवं वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को विस्तृत ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन का ध्यान इस महत्वपूर्ण विसंगति की ओर आकृष्ट किया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन कल्याण मंत्रालय के पत्र दिनांक 12 मई 2017 एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के पत्र दिनांक 23 मई 2017 के आधार पर 1 जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त केंद्रीय सिविल पेंशनरों की पेंशन को सेवानिवृत्ति के समय पद एवं वेतनमान के आधार पर काल्पनिक निर्धारण कर पुनरीक्षित किया है। एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी का कहना है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा भी सातवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन पुनरीक्षण में केंद्र सरकार के वेतनमान एवं फार्मूले का अनुसरण किया है ऐसी स्थिति में पूर्व 2016 एवं पश्चात 2016 सेवानिवृत पेंशनरों में अंतर करना अन्यायपूर्ण एवं असंगत है ।भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि पेंशन पुनरीक्षण का मूल उद्देश्य बढ़ती महंगाई के अनुरूप सेवानिवृत कर्मचारियों को सम्मानजनक एवं पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

महंगाई भत्ते-सीपीसीटी के विरोध में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

नारेबाजी कर विरोध जताया और जल्द कैशलेस हेल्थ स्कीम लागू करने की मांग की

भोपाल (नप्र)। आठ माह से लंबित महंगाई भत्ते और सीपीसीटी की अनिवार्यता के विरोध में तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन ने मंगलवार को मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नारेबाजी कर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया और जल्द कैशलेस हेल्थ स्कीम लागू करने की मांग की।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि प्रदर्शन में संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने प्रदेश में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की मांग की।

नए कर्मचारियों को 100 प्रतिशत वेतन देने की मांग

कर्मचारियों ने नवनियुक्त कर्मचारियों को तीन साल तक 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन देने के प्रावधान को खत्म करने की मांग की। संघ का कहना है कि इस व्यवस्था के कारण प्रत्येक कर्मचारी को करीब 1.74 लाख से 4 लाख रुपए तक का आर्थिक नुकसान होता है।

कैशलेस इलाज अनिवार्यता खत्म करने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इसका लाभ नहीं मिल रहा है। संघ ने योजना को जल्द लागू करने की मांग की।

कर्मचारियों ने कहा कि सीधी भर्ती में सीपीसीटी की अनिवार्यता रखी जा सकती है, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति और चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए इसकी बाध्यता खत्म की जानी चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति में भी सीपीसीटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की गई। इसके अलावा कर्मचारियों ने ई-अटेंडेंस व्यवस्था खत्म करने की मांग भी उठाई। प्रदर्शन का नेतृत्व संघ के प्रदेश अध्यक्ष अतुल मिश्रा ने किया। इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष सलीम खान सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

हाईकोर्ट के आदेश पर भोपाल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

निशातपुरा में प्राइवेट जमीन पर बने 11 मकान तोड़े, भारी पुलिस बल रहा मौजूद

भोपाल (नप्र)। भोपाल के निशातपुरा में हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां प्राइवेट जमीन पर बने 11 मकानों को चार पोकलेन मशीनों के जरिए जमींदोज कर दिया गया। कोई हंगामा न हो, इसलिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

बैरागढ़ एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई हो रही है। तहसीलदार हर्षविक्रम सिंह समेत अन्य राजस्व अधिकारियों को भी कार्रवाई में लगाया गया है। जानकारी के अनुसार, यह अतिक्रमण करीब 35 साल बाद हटा है। जिला प्रशासन पहले भी कार्रवाई करने के लिए मैदान में उतरा था, लेकिन विरोध के चलते कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इस पर पुलिस और प्रशासन की सख्त कार्रवाई की चेतावनी के बाद यह कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार, अविनाश जौहरी की जमीन पर कई सालों से अतिक्रमण हो गया। खास बात ये है कि जमीन की रजिस्ट्री हो गई और तीन मंजिला मकान तक बन गए थे। अपनी 0.75 एकड़ जमीन को कब्जामुक्त करवाने के लिए जौहरी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

उनकी जमीन पर 11 मकान बने थे। हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर, नगर निगम और पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। कहा था कि जिन पक्षकारों के स्थगन है, उन्हें छोड़कर बाकी पर कार्रवाई की जाए। इसके चलते मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम भारी भरकम पुलिस अमले के साथ मैदान में उतरी और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान मौजूद बैरागढ़ एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव, तहसीलदार हर्षविक्रम सिंह व पुलिस बल मौजूद थे।

सरकारी जमीन पर भी बने घर- यहां पर 0.3 एकड़ सरकारी जमीन भी है। इस पर भी अवैध कब्जा है। कुछ पर हाईकोर्ट का स्टे है। इसलिए फिलहाल यहां कार्रवाई नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने मंगलवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) से कैलारस- सबलगढ़ -बीरपुर रेलखंड के उद्घाटन और ग्वालियर कैलारस मेमू ट्रेन के बीरपुर स्टेशन तक विस्तार के शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए।

संत रविदास जी के सामाजिक समरसता एवं समानता के संदेश को प्रत्येक पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा ध्येय : राज्यमंत्री गौर

बरखेड़ा भेल से संत रविदास कलश वंदन यात्रा का किया शुभारंभ

भोपाल (नप्र)। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जन्म जयंती वर्ष के पावन अवसर पर भोपाल स्थित श्री संत रविदास मंदिर, डी-सेक्टर बरखेड़ा भेल से दिव्य 'कलश वंदन यात्रा' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संत रविदास का भक्तिभाव से स्मरण करते हुए यात्रा में अपनी सहभागिता दर्ज कराई।

अंतिम व्यक्ति के उत्थान से साकार हो रहा संत रविदास जी का संकल्प- राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास का संदेश समाज में व्याप्त विषमता को समाप्त कर समरसता और भ्रातृभाव स्थापित करने का है। संपूर्ण समाज उनकी जयंती को अगाध श्रद्धा एवं समर्पण भाव से मना रहा है। आज की महती आवश्यकता यह है कि उनके कालजयी एवं उदात्त विचारों को भावी पीढ़ियों के अंतर्मन तक संप्रेषित किया जाए। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मूलमंत्र सबका साथ, सबका विकास संत रविदास के विचारों की ही प्रतिध्वनि है। समाज के अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाकर उसे प्रथम पंक्ति में प्रतिष्ठापित करना ही संत रविदास के संकल्पों की वास्तविक सिद्धि है। उनके चरणकमलों में शीश नवाकर उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करना हम सभी के लिए परम गौरव का विषय है।

सागर में 102 करोड़ की लागत से आकार ले रहा भव्य संत रविदास मंदिर- राज्य सरकार द्वारा संत रविदास जी के विचारों के व्यापक प्रसार और उनके सम्मान में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए श्रीमती गौर ने कहा कि सागर में 102 करोड़ रुपये की लागत से संत रविदास के अलौकिक मंदिर एवं स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेशभर में स्थित धार्मिक स्थलों तथा देवालयों के पुनरुद्धार एवं जीर्णोद्धार का कार्य भी निरंतर जारी है। समारोह में श्री संत रविदास मंदिर परिसर में 15 लाख रुपये की लागत से होने वाले विभिन्न विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का भुमि-पूजन हुआ। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं और नागरिक समाज ने संत रविदास के दर्शाए मार्ग पर चलने तथा सामाजिक समरसता के ताने-बाने को और अधिक सुदृढ़ बनाने का सामूहिक संकल्प लिया।

प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लिए गए संकल्पों की सिद्धि में हरसंभव योगदान देगा मप्र : सीएम

औद्योगिक क्लस्टर विकास के लिए लागू भव्य योजना में सर्वाधिक प्रस्ताव भेजने में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जो संकल्प घोषित किये गये हैं, उनकी सिद्धि में मध्यप्रदेश अपना अधिकतम योगदान देगा। पांच से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा, बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर अच्छा खिलाड़ी बनाया जायेगा। युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग कराने का निर्णय लिया गया है, जिसमें संसाधनों को जोड़ कर नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का पूरा नेटवर्क खड़ा किया जायेगा। आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग दी जायेगी जिससे युवाओं में एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य हो। नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक बड़ा अभियान चलाया जायेगा। इसमें आध्यात्मिक हस्तियों, स्वयं सेवकों, समाज सेवियों आदि सभी का सहयोग मिलेगा। सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा किया जायेगा। आधुनिक संकटों से नागरिकों की रक्षा करने के लिए बड़ा वॉलंटरी फोर्स बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रिपरिषद् की बैठक से पहले मंत्रिगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि बैठक में धार जिले में विकसित हो रहे देश के पहले मेगा पीएम मित्र पार्क के विकास कार्यों की सराहना की गई। देश में 7 पीएम मित्र पार्क बनने हैं, जिसमें से पहला मध्यप्रदेश को मिला है। इसके भूमि-पूजन के साथ उसी दिन सभी भूखंड आवंटित हो गए। विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में भी देश की प्रतिष्ठित कंपनियों ने अपनी ईकाई स्थापित की हैं। यहां कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल सहित सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हॉस्टल का काम 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में एक्सप्रेस वे आधारित औद्योगिक विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है।

प्रदेश में ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन को 50 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि सप्त धारा की पहली शक्ति मैन्युफैक्चरिंग पावर, दूसरी शक्ति कृषि और फूड प्रोडक्शन, तीसरी शक्ति टेक्नोलॉजी और इनोवेशन,चौथी शक्ति गति शक्ति, पांचवी शक्ति रक्षा शक्ति और छठी शक्ति ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनामी है, जो ग्रीन जॉब्स को भी जन्म देती है। सातवीं शक्ति के रूप में आध्यात्म, योग और आयुर्वेद के माध्यम से हेल्थ, क्रॉफ्ट, संस्कृति, क्रिएटिव फिल्में, गेमिंग और डिजिटल इकोनॉमी के लिए काम करने की अच्छी संभावनाएं हैं। मध्यप्रदेश में अभी 30 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, इसे 50 प्रतिशत तक लेकर जाने का लक्ष्य रखा है।

राज्य सरकार ने 11 औद्योगिक क्लस्टर के लिए भूमि उपलब्ध कराई

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि नई दिल्ली में 17 अगस्त को उन्होंने केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ 'भव्य' योजना के अंतर्गत बैठक में सहभागिता की। भव्य योजना 33 हजार 660 करोड़ रुपए की है, जिसके माध्यम से देश में औद्योगिक विकास की कल्पना की गई है। इसमें केंद्र सरकार ने देशभर में 100 औद्योगिक क्लस्टर का बेल्ट तैयार करने की बात कही है, जिसमें से पहले चरण में 20 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इसके लिए सभी राज्यों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं, जिससें भूमि आवंटन की बात कही गई है। मध्यप्रदेश सरकार ने 11 औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए भूमि आवंटित कर प्रस्ताव बैठक में दिए। सर्वाधिक प्रस्ताव भेजने में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा।

एट्रिब्यूट-वाइज ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू

341 उच्च शिक्षा संस्थानों के आईक्यूएसी समन्वयकों एवं संबंधित प्रभारियों को गुणवत्ता मानकों पर दिया जाएगा प्रशिक्षण

भोपाल (नप्र)। उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए गठित एसएएसी के तहत अब एट्रिब्यूट-वाइज ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के आईक्यूएसी समन्वयकों और संबंधित एट्रिब्यूट प्रभारियों को मूल्यांकन प्रक्रिया, गुणवत्ता संकेतकों, आवश्यक दस्तावेजीकरण और संस्थागत तैयारियों के संबंध में व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना है। ऑनलाइन प्रशिक्षण की शुरुआत 18 अगस्त को पाठ्यक्रम डिजाइन से होगी। इसके बाद 20 अगस्त को अधोसंरचना, 8 सितंबर को फैकल्टी संसाधन, 9 सितंबर को वित्तीय संसाधन एवं प्रबंधन, 16 एवं 17 सितंबर को अधिगम एवं शिक्षण, 18 सितंबर को विस्तारित सह-पाठ्यक्रमीय सहभागिता, 29 सितंबर को शासन एवं प्रशासन, 30 सितंबर को विद्यार्थी परिणाम, 8 अक्टूबर को अनुसंधान एवं नवाचार परिणाम तथा 9 अक्टूबर को सततता परिणाम एवं हरित पहल पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में प्रत्येक एट्रिब्यूट से संबंधित गुणवत्ता मानकों, आवश्यक सूचनाओं, अभिलेखों, दस्तावेजों तथा मूल्यांकन के लिए जरूरी साक्ष्यों के संबंध में विस्तार से मार्गदर्शन दिया जाएगा। इससे संस्थानों को अपने स्तर पर संबंधित जानकारी व्यवस्थित करने और मूल्यांकन के लिए आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने में सहायता मिलेगी। प्रशिक्षण माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। इसमें प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के आईक्यूएसी समन्वयकों एवं संबंधित एट्रिब्यूट प्रभारियों की सहभागिता रहेगी। प्रशिक्षण के बाद संबंधित संस्थानों द्वारा आवश्यक जानकारी एसएएसी पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा में दर्ज की जाएगी। एसएएसी के प्रथम चरण में प्रदेश के 341 शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों का राज्य स्तरीय मूल्यांकन किया जाना है।

जन विश्वास अभियान में 21 अगस्त को टीकमगढ़ जिले के भ्रमण पर रहेंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जन विश्वास अभियान के अंतर्गत जारी गतिविधियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के कारण न केवल जमीनी समस्याएं पता चल रही हैं, बल्कि निराकरण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अभियान का तीसरा शुक्रवार 21 अगस्त को आ रहा है। इस दिन मुख्यमंत्री डॉ. यादव का टीकमगढ़ जिले का भ्रमण निर्धारित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रीगण को जन विश्वास अभियान के अंतर्गत फील्ड भ्रमण अवश्य करने के लिए निर्देशित किया।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में डिंडौरी मॉडल का अनुसरण करें सभी जिले

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार की अनेक महत्वाकांक्षी हितग्राही मूलक योजनाओं में मध्यप्रदेश देशभर में अग्रणी है। प्रदेश ने कृषि वर्ष में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री धन-धान्य क्रियान्वयन योजना में प्रदेश का डिण्डौरी जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पर आया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि विभाग और डिण्डौरी जिले की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अन्य सभी जिले भी डिण्डौरी मॉडल का अनुसरण कर इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

संपादकीय

टीम नवीन: बड़ी चुनौतियां

नितिन नवीन के भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के आठ माह बाद उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हो गई है। इस टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2029 का लोकसभा चुनाव बहुमत के साथ जीतने और इसके पूर्व यूपी सहित करीब एक दर्जन राज्यों में सत्ता हासिल करने अथवा पार्टी को फिर से सरकार में लौटाने की है। इस टीम में तुलनात्मक रूप से युवा चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी गई है, जब कि महिलाओं की संख्या भी पूर्ववर्ती कार्यकारिणियों के मुकाबले ज्यादा है। हालांकि पार्टी जिस 33 फीसदी राजनीतिक आरक्षण पर जोर दे रही है, उसकी तुलना में यह अभी भी कम है। इस टीम नवीन में कुल 68 सदस्य हैं।

नई कार्यकारिणी की घोषणा के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तीन राज्यों के नए प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है। इसमें बिहार चुनाव जिताने वाले विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी नियुक्त किया है। पंजाब की जिम्मेदारी सतीश पूनिया को दी गई है। गुजरात का जिम्मा तरुण चुग को सौंपा गया है। इन तीनों राज्यों में अगले साल चुनाव हैं। नई कार्यकारिणी में 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महासचिव, 16 राष्ट्रीय सचिव हैं। उपाध्यक्षों में वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव और प्रोफ़ेसर तारिक़ मंसूर जैसे नाम शामिल हैं। वहीं, राष्ट्रीय महासचिव के लिए आठ नाम, राष्ट्रीय सचिव के लिए 16 नामों की घोषणा की गई है। सात अलग-अलग मोर्चा अध्यक्षों में सबसे ज़्यादा चर्चा कुंवर बासित अली और हेमांग जोशी की है। कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का और हेमांग जोशी को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। नया सोशल मीडिया इंचार्ज दीपक म्हस्के को बनाया गया है जबकि इस पद पर अब तक चर्चित नेता अमित मालवीय थे। उनकी छुट्टी हो गई है। प्रोफेसर तारिक मंसूर 2023 में ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे। वो वर्तमान में यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी रह चुके हैं। नई कार्यकारिणी में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दी गई है। जब संगठन के राष्ट्रीय महासचिव की ज़िम्मेदारी बीएल संतोष के पास ही रखी गई है। इसी प्रकार 16 राष्ट्रीय सचिवों में केरल से के सुरेंद्रन और अनिल एंटनी का नाम हैं। केन्द्रीय कार्यालय प्रभारी के पद पर तरुण चुग, केन्द्रीय कार्यालय सचिव के पद पर महेंद्र पांडे, नॉर्थ ईस्ट कॉर्डिनेटर के पद पर संबित पात्रा और मीडिया संयोजक के पद पर अनिल बलूनी का नाम तय किया गया है। इस कार्यकारिणी में कुल 12 महिलाएं हैं। जिनमें 6 को राष्ट्रीय उपाध्यलक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आठ राष्ट्रीय महासचिवों के नामों में इकलौती महिला स्मृति इरानी शामिल हैं। जबकि 16 राष्ट्रीय सचिवों में तीन महिलाओं के आम आदमी पार्टी के पूर्व रणनीतिकार संदीप पाठक भी राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। नई टीम में नए और पुराने के समन्वय के साथ यह भी ध्यान रखा गया कि ये लोग अपेक्षाकृत युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिलकर काम कर सके। हालांकि जो टीम बनी है, उसकी परफार्मेंस क्षमता पर भी उंगलियां उठ रही हैं। कुछ समीक्षकों की नजर में टीम नवीन इससे कहीं बेहतर हो सकती थी। दूसरे, टीम में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, जिन्हें चुनाव लड़ने और जिताने का खासा अनुभव है, जबकि अगला लोकसभा और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जीतना इस टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यह टीम कैसे परफार्म करेगी, यह इस बात पर निर्भर है कि अध्यकक्ष नितिन नवीन इस टीम के साथ कैसे तालमेल बिठा पाते हैं और सब मिलकर कैसे नतीजे देते हैं।

नजरिया

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

तरक्की की रोशनी में उठते कुछ सवाल

कभी इस मिट्टी ने बेड़ियों की खनक सुनी थी, कभी इसी आकाश ने गुलामी की लंबी रात देखी थी। फिर एक सुबह क्षितिज पर आज़ादी का सूरज उगा और तिरंगे ने हवा से कहा- लहू से सींचे सपनों का, ये हमारा हिंदुस्तान है, हर साँस में बसी शहादत, हर धड़कन में अरमान है। मिली जो आज़ादी हमें, उसे मुकम्मल करना है, सिर्फ़ सरहद नहीं, दिलों को भी आज़ाद करना है।

1947 से 2026 तक भारत ने समय की नदी में बहुत दूर तक सफर तय किया है। कभी अभावों से लड़ते हुए, कभी उपलब्धियों पर इतराते हुए, कभी टूटकर फिर संभलते हुए। उस समय भारत के पास न संसाधन थे, न साधन सीमित थे और समस्याएँ असंख्य थीं, लेकिन आँखों में एक सपना था- ऐसा भारत जहाँ कोई भूखा न सोए, कोई अशिक्षित न रहे, किसी के साथ जन्म, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो और हर नागरिक अपने सम्मान के साथ जीवन जी सके। आज हमारे पास विकास की चमक है, मगर कुछ अँधेरे अब भी शेष हैं। आज 79 वर्ष बाद भारत की तस्वीर निस्संदेह बदली है- विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं ने नई ऊँचाइयाँ छुई हैं। मगर इसी चमक के बीच कुछ सवाल अब भी खड़े हैं। क्या गरीबी, अशिक्षा, भेदभाव, भ्रष्टाचार और सामाजिक बंधनों से हम पूरी तरह मुक्त हो पाए हैं? क्या हमारे विचार सच में स्वतंत्र हैं?

आज 79 वर्ष बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो भारत की यात्रा किसी साधारण यात्रा की तरह नहीं दिखाई देती। यह संघर्षों, उपलब्धियों, असफलताओं, उम्मीदों और अधूरे सपनों से बनी एक लंबी कहानी है। हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन बहुत कुछ अभी भी पाना बाकी है। हमारे हाथ में तकनीक है, अंतरिक्ष तक पहुँच है, विशाल अर्थव्यवस्था है, लोकतांत्रिक संस्थाएँ हैं और दुनिया के मंच पर बढ़ता प्रभाव है; फिर भी कहीं कोई बच्चा भूख से सोता है, कोई किसान चिंता में डूबा है, कोई लड़की अवसरों के अभाव में अपने सपनों को छोटा कर लेती है और कोई गरीब व्यक्ति व्यवस्था के सामने अपनी आवाज़ कमजोर महसूस करता है। इसलिए आज़ादी की 79वीं वर्षगाँठ पर सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या हम सचमुच आज़ाद हैं?

1947 का भारत आज के भारत से बहुत अलग था। अंग्रेजी शासन ने देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, शिक्षा और सामाजिक संरचना पर गहरे प्रभाव छोड़े थे। विभाजन की त्रासदी ने लाखों लोगों को विस्थापित किया और असंख्य परिवारों को अपने घर, अपने प्रियजन और अपनी स्मृतियाँ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। देश के सामने गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, खाद्यान्न संकट और कमजोर औद्योगिक आधार जैसी बड़ी चुनौतियाँ थीं। गाँवों में जीवन कठिन था और शहर भी आधुनिक सुविधाओं से बहुत दूर थे। लेकिन उस कठिन समय में भारत के पास एक अमूल्य संपत्ति थी- आशा। यह विश्वास था कि अब देश अपने निर्णय स्वयं करेगा। संविधान निर्माण के साथ नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिला। लोकतंत्र को अपनाना अपने आप में एक महान प्रयोग था। दुनिया के कई देशों को स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रखने में कठिनाइयाँ आईं, लेकिन भारत ने लोकतंत्र की राह को अपना आधार बनाया। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

आज के भारत को 1947 के भारत की तुलना में देखें तो परिवर्तन की तस्वीर अत्यंत व्यापक है। जिस देश में कभी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष था, वही देश आज विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, संचार, अंतरिक्ष और उद्योग के अनेक क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुका है। सड़कों, रेल, बिजली, दूरसंचार और डिजिटल सेवाओं के विस्तार ने जीवन को बदल दिया है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने सूचना को घर-घर पहुँचा दिया है। बैंकिंग और डिजिटल भुगतान ने आर्थिक व्यवहार को नई गति दी है। भारतीय युवा आज दुनिया की बड़ी कंपनियों में नेतृत्व कर रहे हैं और देश के छोटे शहरों से निकलने वाली प्रतिभाएँ वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी तस्वीर बदली है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों का विस्तार हुआ है। पहले जहाँ शिक्षा कुछ विशेष वर्गों तक सीमित थी, आज करोड़ों बच्चे स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुँच रहे हैं। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी बढ़ी है। लड़कियाँ विज्ञान, खेल, प्रशासन, सेना, राजनीति, उद्योग और कला सहित हर क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध कर रही हैं। यह परिवर्तन केवल आँकड़ों का परिवर्तन नहीं है; यह उस मानसिकता के बदलने का संकेत है जिसमें कभी लड़की के सपनों को उसके घर की चारदीवारी से आगे जाने की अनुमति नहीं थी।

आज़ादी के बाद भारत ने गरीबी कम करने की दिशा में लंबी यात्रा तय की है। आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर, सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार ने करोड़ों लोगों के जीवन में सुधार किया है। आज देश में एक बड़ा मध्यम वर्ग है, उपभोग की क्षमता बढ़ी है और अनेक परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। फिर भी गरीबी केवल खाली जेब का नाम नहीं है। गरीबी का अर्थ अवसरों की कमी भी है। जब किसी बच्चे के पास अच्छी शिक्षा नहीं होती, जब किसी परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है, जब किसी युवा के पास योग्यता होने के बावजूद रोजगार नहीं होता, तब गरीबी अपना नया चेहरा दिखाती है। आज भी हमारे समाज में आर्थिक असमानता एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ चमकते महानगर हैं, ऊँची इमारतें हैं और आधुनिक जीवनशैली है; दूसरी तरफ ऐसे गाँव और बस्तियाँ हैं जहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष जारी है। इसलिए गरीबी के खिलाफ लड़ाई केवल आय बढ़ाने की नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन और समान अवसर देने की लड़ाई भी है।

1947 में भारत की साक्षरता दर बहुत कम थी। आज शिक्षा का प्रसार कहीं अधिक व्यापक है। स्कूलों की संख्या बढ़ी है, उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ है और डिजिटल माध्यमों ने ज्ञान की पहुँच को आसान बनाया है। यह परिवर्तन भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में गिना जाना चाहिए। लेकिन शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर पहचानना नहीं है। शिक्षा वह शक्ति है जो मनुष्य को प्रश्न करना, समझना, विवेक से निर्णय लेना और सही-गलत के बीच अंतर करना सिखाती है। आज हमारे सामने शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगारपरकता और समान अवसर की चुनौती है। एक बच्चा महँगे निजी विद्यालय में आधुनिक संसाधनों के साथ पढ़ता है और दूसरा बच्चा ऐसे विद्यालय में जहाँ शिक्षक और संसाधन दोनों सीमित हैं, तो दोनों के सामने भविष्य की दौड़ समान कैसे होगी? जब शिक्षा अवसरों की सीढ़ी बनने के बजाय आर्थिक स्थिति का आईना बन जाए, तब हमें अपने विकास की दिशा पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

भारत का संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। कानून की दृष्टि से किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन सामाजिक जीवन में भेदभाव के अनेक रूप आज भी दिखाई देते हैं। जातिगत पूर्वाग्रह, धार्मिक अविश्वास, लैंगिक असमानता और आर्थिक स्थिति के आधार पर सामाजिक दूरी हमारे समाज की वास्तविक चुनौतियाँ हैं। हम अक्सर कहते हैं कि भारत बदल गया है, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब किसी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और चरित्र से तय होगी। जब बेटी के जन्म पर चिंता नहीं, उत्सव होगा। जब किसी गरीब बच्चे को उसके कपड़ों से नहीं, उसकी प्रतिभा से पहचाना जाएगा। जब अलग विचार रखने वाला व्यक्ति शत्रु नहीं माना जाएगा। आज़ादी का अर्थ तभी पूर्ण होगा जब मनुष्य के भीतर बैठा भेदभाव भी आज़ाद हो।

भ्रष्टाचार केवल सरकारी कार्यालय की मेज के नीचे होने वाला लेन-देन नहीं है। यह तब भी पैदा होता है जब कोई व्यक्ति नियम तोड़कर अपना काम निकलवाना चाहता है। जब हम सुविधा के लिए कानून को नजरअंदाज करते हैं, जब हम रिश्वत देने को सामान्य मान लेते हैं और जब सार्वजनिक संपत्ति को अपना नहीं समझते, तब हम भ्रष्टाचार की संस्कृति को मजबूत करते हैं। भ्रष्टाचार देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाता है, विकास की गति को प्रभावित करता है और नागरिकों के विश्वास को कमजोर करता है। तकनीक और पारदर्शिता ने भ्रष्टाचार के कई रास्तों को कठिन बनाया है, लेकिन केवल व्यवस्था बदलने से समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। नागरिक की ईमानदारी भी उतनी ही जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि देश ईमानदार हो, तो हमें अपनी छोटी-छोटी सुविधाओं के लिए बेईमानी को स्वीकार करना बंद करना होगा।

विदेशी शासन समाप्त हो गया, लेकिन क्या गुलामी पूरी तरह समाप्त हो गई? यह सवाल हमें भीतर तक झकझोरता है। मानसिक गुलामी वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेने के बजाय दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करता है। जब हम अपनी भाषा, संस्कृति या ज्ञान को केवल इसलिए कमतर समझते हैं क्योंकि वह पश्चिमी नहीं है, तब मानसिक गुलामी दिखाई देती है। जब समाज की रूढ़ियाँ हमारे सपनों की सीमा तय करती हैं, तब भी हम मानसिक रूप से गुलाम होते हैं। आज सोशल मीडिया ने इस समस्या को नया रूप दिया है। हम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगे हैं। लाइक, कमेंट और फॉलोअर हमारी खुशी का पैमाना बनने लगे हैं। एल्गोरिदम हमारी पसंद को प्रभावित करते हैं और कई बार हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। तकनीक ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, लेकिन विवेक की स्वतंत्रता हमें स्वयं अर्जित करनी होगी।

भारत की संस्कृति उसकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। परंपराएँ हमें इतिहास और जड़ों से जोड़ती हैं। परिवार और सामाजिक संबंध हमारे जीवन को सहारा देते हैं। लेकिन हर परंपरा सही हो, यह जरूरी नहीं। जो परंपरा मनुष्य को सम्मान देती है, उसे बचाना चाहिए, जो परंपरा किसी की स्वतंत्रता छीनती है, उस पर प्रश्न करना चाहिए

इसलिए 15 अगस्त को जब तिरंगा आकाश में लहराए, तो हमें केवल गर्व से उसे देखना नहीं चाहिए, बल्कि अपने भीतर भी झाँकना चाहिए। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या मेरे व्यवहार में भारत की आज़ादी दिखाई देती है? क्या मैं दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करता हूँ? क्या मैं भेदभाव से मुक्त हूँ? क्या मैं ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाता हूँ? क्या मैं देश को केवल सरकार से अपेक्षाएँ रखकर देखता हूँ या स्वयं भी उसके निर्माण में योगदान देता हूँ? क्योंकि भारत की आज़ादी की सबसे सुंदर तस्वीर संसद की इमारतों में नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन में दिखाई देगी। जिस दिन किसी बच्चे की गरीबी उसके सपनों को नहीं रोक पाएगी, जिस दिन शिक्षा अमीरी-गरीबी की दीवारों से ऊपर उठेगी, जिस दिन जाति और धर्म मनुष्य की कीमत तय नहीं करेंगे, जिस दिन भ्रष्टाचार को चतुराई नहीं बल्कि शर्म समझा जाएगा और जिस दिन भारतीय अपने भीतर की हीनता, भय और संकीर्णता से मुक्त होकर खड़ा होगा, उस दिन हम कह सकेंगे कि 1947 में मिली आज़ादी ने अपना सच्चा अर्थ पा लिया है।

आज तिरंगा हमें पुकार रहा है। वह केवल तीन रंगों का ध्वज नहीं, बल्कि हमारे अतीत के बलिदानों, वर्तमान की जिम्मेदारियों और भविष्य के सपनों का प्रतीक है। 1947 ने हमें आज़ाद देश दिया था; अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह आने वाली पीढ़ियों को सच्चा, समतामूलक, शिक्षित, संवेदनशील और आत्मविश्वासी भारत दे। यही आज़ादी का सम्मान है, यही स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को सच्ची श्रद्धांजलि है और यही उस भारत की ओर हमारा अगला कदम है, जिसका सपना कभी करोड़ों आँखों ने देखा था।

पर्यावरण

कुमार सिद्धार्थ

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

डिजिटल विकास: पानी, ऊर्जा और पर्यावरण का सवाल

पिछली एक शताब्दी पर नज़र डालें तो औद्योगिक विकास की पहचान विशाल कारखानों, ऊँची चिमनियों, इस्पात संयंत्रों और मशीनों की गूंज से होती थी। वही किसी देश की आर्थिक शक्ति और औद्योगिक प्रगति के प्रतीक माने जाते थे। लेकिन इक्कीसवीं सदी में विकास का चेहरा बदल चुका है। आज विशाल, शांत और अत्याधुनिक इमारतें नई अर्थव्यवस्था की धुरी बन रही हैं। इनमें न मशीनों का शोर सुनाई देता है, न धुएँ के गुबार उठते हैं, फिर भी दुनिया की लगभग हर डिजिटल गतिविधि की नींव इन्हीं पर टिकी है। इन्हीं नई आधुनिक इमारतों को हम च्डेटा सेंटरज्‌ के नाम से जानते हैं। आज मोबाइल से किया गया भुगतान, किसी विद्यार्थी की ऑनलाइन कक्षा, अस्पताल का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, किसान के मोबाइल पर पहुँचा मौसम का पूर्वानुमान, सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीर या कोई भी संवाद इनमें से कोई भी गतिविधि डेटा सेंटरों के बिना संभव नहीं है। हर डिजिटल क्रिया अंततः किसी न किसी डेटा सेंटर तक पहुँचती है, जहाँ सूचनाएँ संग्रहित होती हैं, उनका विश्लेषण होता है और वे कुछ ही क्षणों में हमारे पास वापस लौट आती हैं।

यही वजह है कि डिजिटल दुनिया जितनी आभासी और अदृश्य दिखाई देती है, उसकी बुनियाद उतनी ही ठोस और वास्तविक है। यह केवल इंटरनेट या सॉफ्टवेयर का संसार नहीं, बल्कि विशाल डेटा सेंटरों, लाखों सर्वरों, निरंतर बिजली आपूर्ति, उच्च क्षमता वाले संचार नेटवर्क और बड़ी मात्रा में ऊर्जा तथा जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित विशाल भौतिक अवसंरचना है।

पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस पूरी व्यवस्था को नई गति दी है। चैटबॉट, भाषा अनुवाद, चित्र निर्माण, वीडियो विश्लेषण, चिकित्सा अनुसंधान और वैज्ञानिक गणनाओं जैसे कार्यों के लिए पहले से कहीं अधिक कंप्यूटिंग क्षमता की आवश्यकता पड़ रही है। इस वजह से दुनिया भर में नए डेटा सेंटरों के निर्माण की होड़ शुरू हो गई है।

अंतरराष्ट्रीय शोध अध्ययनों के अनुसार वर्तमान में विश्व में लगभग 11,800 डेटा सेंटर संचालित हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और देश एशिया के प्रमुख डेटा सेंटर बाज़ारों में शामिल हो चुका है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, क्लाउड सेवाओं, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा और सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस विस्तार को और गति दी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि डेटा सेंटर आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए उतने ही आवश्यक हैं, जितने कभी सड़कें, रेलमार्ग और बिजलीघर। वे निवेश आकर्षित करते हैं, रोजगार सृजित करते हैं और डिजिटल सेवाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं। लेकिन हर 'विकास' अपने साथ कुछ अनदेखे प्रश्न भी लेकर आता है। लंबे समय तक डेटा सेंटरों की चर्चा केवल उनकी बिजली खपत तक सीमित रही। अब वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और नीति-निर्माताओं का ध्यान एक ऐसे प्राकृतिक संसाधन की ओर जा रहा है, जिसकी चर्चा अक्सर छूट जाती है, वह है जल।

डिजिटल दुनिया की अदृश्य प्यास- हम मानते हैं कि हमारा डेटा 'क्लाउड' में सुरक्षित है। क्लाउड कोई काल्पनिक स्थान नहीं, बल्कि हजारों सर्वरों से भरे विशाल डेटा सेंटरों का नेटवर्क है। हर ई-मेल, हर डिजिटल भुगतान, हर वीडियो, हर ऑनलाइन खोज और हर एआई अनुरोध इन्हीं सर्वरों पर संसाधित होता है। ये सर्वर दिन-रात लगातार काम करते हैं। जितनी अधिक गणनाएँ होती हैं, उतनी ही अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। यदि यह तापमान नियंत्रित न किया जाए तो सर्वर की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है, उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और डिजिटल सेवाएँ बाधित हो सकती हैं। इसलिए शीतलन (कूलिंग) डेटा सेंटर की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

बड़े डेटा सेंटरों में सर्वरों को सुरक्षित तापमान पर बनाए रखने के लिए पानी आधारित कूलिंग टावर, चिलर और वाष्पीकरण आधारित शीतलन प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। पानी गर्मी को तेजी से अवशोषित करता है, इसलिए यह बड़े डेटा सेंटरों के लिए प्रभावी माध्यम माना जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि डिजिटल सुविधाओं की बढ़ती माँग के साथ पानी की माँग भी बढ़ने लगती है। यही वह प्रश्न है, जिसने पूरी दुनिया में नई बहस शुरू कर दी है। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार ऐसे समय में हो रहा है, जब दुनिया पहले से ही जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है? और यदि हाँ, तो क्या भविष्य का डिजिटल विकास जल सुरक्षा के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ सकेगा?

इन सवालों के उत्तर केवल तकनीकी नहीं, बल्कि पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक भी है। आने वाले वर्षों में यही तय करेगा कि डिजिटल प्रगति वास्तव में टिकाऊ विकास का आधार बनती है या प्राकृतिक संसाधनों पर एक नया दबाव।

डेटा सेंटर कितना पानी पीते हैं?

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार लगभग 100 मेगावाट क्षमता वाला एक हाइपरस्केल डेटा सेंटर केवल शीतलन के लिए प्रतिदिन लगभग 20 लाख लीटर पानी तक उपयोग कर सकता है। यह मात्रा कई छोटे कस्बों की दैनिक जल आवश्यकता के बराबर हो सकती है। पानी का उपयोग केवल शीतलन टावरों में ही नहीं होता, बल्कि आर्द्रता नियंत्रण और अन्य सहायक प्रणालियों में भी किया जाता है।

भारत में ऊर्जा, पर्यावरण एवं जलवायु पर कार्य करने वाली संस्था सीईईडब्ल्यू (CEEW) का अनुमान है कि वर्ष 2024 में देश के डेटा सेंटरों ने लगभग 150 अरब लीटर पानी का उपयोग किया। यदि वर्तमान विस्तार की गति बनी रही, तो 2030 तक यह खपत दोगुने से अधिक हो सकती है। यह अनुमान केवल उद्योग के आकार का नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की नीति संबंधी चुनौती का भी संकेत देता है। हालाँकि यह भी समझना आवश्यक है कि सभी डेटा सेंटर समान मात्रा में पानी उपयोग नहीं करते। कुछ आधुनिक केंद्र कम जल-आधारित या लगभग जल-रहित शीतलन तकनीकों की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि पुराने केंद्र अपेक्षाकृत अधिक पानी पर निर्भर हैं। इसलिए भविष्य की दिशा केवल डेटा सेंटरों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी जल-दक्षता भी तय करेगी।

एआई ने क्यों बढ़ाई चुनौती?- कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने डेटा सेंटरों की भूमिका को पूरी तरह बदल दिया है। पहले अधिकांश डेटा सेंटर ई-मेल, वेबसाइट, क्लाउड स्टोरेज और सामान्य इंटरनेट सेवाओं के लिए बनाए जाते थे। अब उन्हें बड़े भाषा मॉडल, मशीन लर्निंग, वीडियो विश्लेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान और जटिल गणनाओं का भार भी उठाना पड़ रहा है।

एआई आधारित प्रोसेसर पारंपरिक सर्वरों की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं और अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं। जिसके कारण शीतलन प्रणालियों पर दबाव बढ़ता है। आज डेटा सेंटरों की योजना केवल बिजली उपलब्धता के आधार पर नहीं बनाई जा रही, बल्कि स्थानीय तापमान, जल उपलब्धता और जलवायु जोखिम को भी ध्यान में रखा जा रहा है। वास्तव में एआई ने नई विडंबना पैदा कर दी है। एक ओर यह जलवायु परिवर्तन, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसी समस्याओं के समाधान में मदद कर सकता है, दूसरी ओर यदि उसकी आधारभूत संरचना संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करेगी तो वही तकनीक पर्यावरणीय दबाव भी बढ़ा सकती है।

भारत के सामने दोहरी चुनौती- भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सरकार डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन दे रही है। दूसरी ओर देश के अनेक हिस्से पहले से ही जल संकट का सामना कर रहे हैं। अनियमित मानसून, घटता भूजल, बढ़ते तापमान और तेजी से बढ़ते शहर जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं।

यही कारण है कि भारत के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर डिजिटल अवसंरचना का विस्तार आवश्यक है, दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि यह विस्तार स्थानीय जल संसाधनों की कीमत पर न हो। यदि भविष्य के डेटा सेंटर ऐसे क्षेत्रों में स्थापित होते हैं जहाँ पहले से ही पेयजल संकट है, तो उद्योग और स्थानीय समुदायों के बीच संसाधनों को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अब डेटा सेंटरों की योजना को केवल निवेश और रोजगार के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जल सुरक्षा, शहरी नियोजन और जलवायु अनुकूलन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है।

दुनिया क्या सीख रही है?- दुनिया की बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ इस चुनौती को स्वीकार कर चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अन्य कंपनियाँ ऐसे डेटा सेंटर विकसित कर रही हैं जिनमें कम पानी का उपयोग हो, उपचारित अपशिष्ट जल का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए और वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया जाए। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि उसने पिछले दो दशकों में अपने डेटा सेंटरों की वॉटर यूज़ इफेक्टिवनेस में लगभग 90 प्रतिशत सुधार किया है।

यूरोप और अमेरिका के कई क्षेत्रों में अब नए डेटा सेंटरों की स्वीकृति देते समय केवल बिजली की उपलब्धता नहीं देखी जाती, बल्कि यह भी आकलन किया जाता है कि उनका स्थानीय जल संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि भविष्य में डेटा सेंटरों की सफलता केवल उनकी कंप्यूटिंग क्षमता से नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा और जल दक्षता से भी आँकी जाएगी। भारत के पास मौका है कि वह डेटा सेंटर उद्योग को ऐसी दिशा दे, जो डिजिटल विकास और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करे। इसके लिए डेटा सेंटरों की स्थापना की प्रक्रिया में जल उपलब्धता और जल प्रभाव आकलन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। जिस प्रकार बड़ी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन आवश्यक होता है, उसी प्रकार बड़े डेटा सेंटरों के लिए स्थानीय जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन भी नीति का हिस्सा होना चाहिए।

केवल जल नहीं, ऊर्जा भी उतनी ही महत्वपूर्ण- यह भी गौरतलब है कि डेटा सेंटरों पर चर्चा अक्सर पानी तक सीमित रह जाती है, जबकि उनका ऊर्जा उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार के साथ दुनिया भर में बिजली की माँग तेजी से बढ़ रही है। यदि यह ऊर्जा कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त होगी, तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा और जलवायु परिवर्तन की चुनौती और गंभीर होगी।

इसलिए भविष्य का टिकाऊ डेटा सेंटर वह होगा, जो केवल कम पानी ही नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा का भी उपयोग करे। सौर और पवन ऊर्जा, ऊर्जा-कुशल सर्वर, उन्नत चिप प्रौद्योगिकी तथा स्मार्ट कूलिंग सिस्टम इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डिजिटल अवसंरचना का भविष्य केवल अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों में नहीं, बल्कि अधिक संसाधन-दक्ष प्रणालियों में निहित है।

विकास की नई कसौटी- इक्कीसवीं सदी का विकास केवल तकनीकी विस्तार का नाम नहीं है। वह इस बात की भी परीक्षा है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कितनी जिम्मेदारी से करते हैं। यदि डिजिटल विकास की कीमत सूखते भूजल, बढ़ते जल संघर्ष और पर्यावरणीय असंतुलन के रूप में चुकानी पड़े, तो वह विकास लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकता। इसलिए अब विकास का नया सूत्र केवल 'डिजिटल फर्स्ट' नहीं, बल्कि 'डिजिटल एंड सस्टेनेबल' होना चाहिए।

डिजिटल भारत का सपना केवल तेज़ इंटरनेट, विशाल डेटा सेंटरों और अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से पूरा नहीं होगा। उसकी सफलता इस बात से भी तय होगी कि इन तकनीकों के विकास में पानी, ऊर्जा और पर्यावरण का कितना सम्मान किया गया। यदि आज दूरदर्शी नीतियाँ अपनाई जाती हैं, तो भारत डिजिटल प्रगति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बीच एक संतुलित मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। यही भविष्य की टिकाऊ अर्थव्यवस्था की वास्तविक पहचान होगी।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

शांतिलाल जैन

लेखक व्यंग्यकार हैं।

जंतर-मंतर: प्रदर्शनकारियों का मक्का

आईए श्रीमान्, ये जो आप देख रहे हैं, आज़ाद भारत में इसे प्रदर्शन करने की सबसे मुफ़ीद जगह माना जाता हैं. प्रदर्शनकारियों का मक्का: दिल्ली का जंतर-मंतर. समझ लें कि ये चित्रकार के सपनों की 'जहाँगीर आर्ट गैलेरी' है जहाँ वह जीवन में कम से कम एकबार अवश्य नुमाइश लगाना चाहता है. किए होंगे आपने जिंदगीभर प्रदर्शन हर जगह, मगर जंतर-मंतर पर नहीं किया तो आपकी प्रोटेस्टर-लाइफ फ़िज़ूल है. जंतर-मंतर देश में पाँच जगह पर हैं, बट डेल्ही इज डिफरेंट. बाकी जगह जंतर-मंतर हैं मगर प्रोटेस्टर्स नहीं हैं. जहाँ प्रोटेस्टर्स हैं वहाँ जंतर-मंतर नहीं हैं. दिल्ली में जंतर-मंतर भी हैं, प्रोटेस्टर्स भी हैं, कवर करनेवाला मेनस्ट्रीम मीडिया भी है और दोगला निज़ाम भी. वह दिन के उजाले में प्रदर्शन की अनुमति देता है, रात के अँधेरे में तम्बू उखाड़ फैंकता है. दिन में लोकतंत्र मज़बूत होता है. लोकतंत्र मज़बूत करने का काम देश में अगले दिन भी बचा रहे इसलिए रात में इसे फिर से कमज़ोर कर देता है. लोकतंत्र में प्रोटेस्ट्स का होना जितना जरूरी है उसे कुचला जाना उससे भी ज्यादा जरूरी है. प्रोटेस्ट करने से डेमोक्रेसी ऑक्सीजन पाती हैं, कुचल दिए जाने से मज़बूत होती है. इसलिए हर सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो लोकतंत्र को पहले कुछ प्राणवायु पा लेने दे फिर उसे कीलें ठुकी हुई लाठियों से मज़बूत बनाने के लिए दौड़ पड़े. प्रहरी ड्रेस पहन पाए तो ठीक, नहीं पहन पाए तो सादी वर्दीवाले साथ में ले जाकर भी डेमोक्रेसी को ताकत दी सकती है. लोकतंत्र सभ्यता के चरम पर तब पहुँचता है जब कोई 'ही' पुलिसवाला किसी 'शी' प्रोटेस्टर के निजी अंगों में करंट छोड़नेवाली बेटन पुश करता है. पत्थर कभी पुलिसवालों को लगता है कभी प्रदर्शनकारियों को. और कोई घायल हो न हो लोकतंत्र लहूलुहान अवश्य होता है.

जंतर-मंतर निज़ाम के लिए भी मुफीद जगह है. जब वह लोकतांत्रिक दिखना चाहता है, तब प्रदर्शन की अनुमति देता है. जब अधिक लोकतांत्रिक दिखना चाहता है तब उसी प्रदर्शन को कुचल देता है. प्रदर्शनकारियों को निज़ाम से डर नहीं लगता, उसके अधिक लोकतांत्रिक हो उठने से लगता है. जंतर-मंतर पर एक सूर्यघड़ी है जो परछाई के झुकाव से बता देती है कि किस प्रोटेस्टर को कब लाठी खिलाना है, कब जूस पिलाना है. इंटेलिजेंस के खगोलशास्त्री सूर्यघड़ी की परछाई देखकर सरकार को बता देते हैं - कौन कब खतरनाक हो सकता है उसे किस दिन, कितने बजकर कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स पर जेल में डालने के योग बन रहे हैं.

एक जंतर-मंतर मेरे शहर उज्जैन में भी है. आलसी और सुस्त. मैंने वहाँ लोकतंत्र मज़बूत होते हुए शायद ही कभी देखा हो. इसीलिए हमारे शहर के पुलिसवाले जब जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर लोकतंत्र मज़बूत होता हुआ देखते हैं तो मज़बूती के यज्ञ में आहुति देने को मचल मचल उठते हैं. हरबार उनकी मचलन निराशा में बदल जाती है. उनके पास लाठी है मगर चार्ज करने के पॉइंट्स नहीं हैं, पैलेट्स हैं, गन हैं, मगर सब्जेक्ट नहीं है. उनकी अपनी आँख का पानी भले सूख गया हो मगर दूसरों की आँखों से आँसू निकल आए, दागने को गैस के गोले हैं. वाटर केनन है मगर चलाने के मौके नहीं है. किस्मतवाली है दिल्ली की पुलिस, लोकतंत्र मज़बूत करने में योगदान दे पा रही है. उसके पास जंतर-मंतर भी है, प्रोटेस्टर्स भी, झूठ बोल जाने की बेशर्मी भी है. और लाठी, गन, गोले तो हैं ही. इसी बरस रिटायर होने जा रहे एक पुलिस अंकल ने कहा - 'लगता है आँसू गैस का गोला छोड़ पाने की हसरत मन में लिए लिए ही रिटायर होना पड़ेगा.'

मैंने कहा - 'अन्याय तो शेष मुल्क में भी कम नहीं हैं पुलिस अंकल, मगर क्या है कि आमजन ने अन्याय के साथ जीना सीख लिया है. समझदार लोग विरोध, निजता और मानवाधिकार जैसी बातों पर लेक्चर सुनने ज़रूर जाते हैं, चच्च-चच्च करते हैं, फिर आत्मतुष्ट होकर बैठ जाते हैं. टीवी पर मंजर देखकर उबलते तो हैं लेकिन शहर के जंतर-मंतर पर पहुँचकर लोकतंत्र बचाने उपायों में शरीक नहीं हो पाते. '

बहरहाल, धैर्य रखे जयपुर, बनारस, उज्जैन की पुलिस और लाठी को तेल नियमित रूप से पिलाती रहे, कौन जाने कब उन्हें उनके जंतर-मंतर पर लोकतंत्र मज़बूत करने के असाइनमेंट में लगा दिया जाए.

तुलसी जयंती पर विशेष

डॉ.मुरलीधर चाँदनीवाला

तुलसी के राम मंदिर में नहीं, लोक-मानस में हैं

तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समय में थे, लेकिन तब भी वे अकबर से ज्यादा ऊपर थे। अपने समय के विख्यात पंडितों और धर्माचार्यों के विरोधों को झेलते हुए भी तुलसीदास जी चुपचाप अपना काम करते रहे, और लोकप्रिय हो गये। तुलसीदास ने कभी मंदिरों का विरोध नहीं किया, लेकिन वे राम को मंदिर से बाहर निकाल लाये। आज भी राम मंदिर में कम, लोक-मानस में ज्यादा बसते हैं, तो इसका श्रेय तुलसीदास को जाता है। यह एक आन्दोलन था, जिसका नेतृत्व अकेले तुलसीदास जी कर रहे थे। वे राम का चरित्र केवल अपने में नहीं, जन-जन के मन में भी बैठा देना चाहते थे। विश्व में तुलसीदास की कविता अकेली है, जिसने अपने कंधों पर यह दायित्व उठाया।

स्वामी तुलसीदास को केवल हिन्दी साहित्य की परिधि में रखकर नहीं देखा जा सकता। वे भक्तिकालीन कवियों के शिरोमणि तो हैं, लेकिन उनमें जनमानस को आन्दोलित कर देने की अनूठी क्षमता है। वे कबीर की तरह आक्रामक नहीं है, लेकिन समाज पर उनका असर कबीर की बनिस्बत ज्यादा हुआ। तुलसीदास लोक-रुचि जानते हैं, समाज का मनोविज्ञान जानते हैं। राम के जीवन को आदर्श मानने वाले तुलसीदास न तो काव्यशास्त्र के नियम तोड़ते हैं, न समाजशास्त्र के। वे प्रचलित परम्पराओं का निर्वाह करते हुए भी समाज को बदलने का तरीका निकालते हैं।

तुलसीदास संस्कृत का अमृत छक कर पी लेने के बाद अचानक संस्कृत से बाहर आ खड़े हुए। वे पूरा रामचरितमानस सरल संस्कृत में लिखने का माद्दा रखते थे, लेकिन उन्होंने अपने ही हाथों से बनी दीवार तोड़ी। अवधी जैसी बहुत ही छोटे से अंचल में बोली जाने वाली अवधी में अपना श्रेष्ठतम देकर उन्होंने अवध के लोगों का दिल जीता। अवध की मिट्टी में खेल कर ही अयोध्या के राम सर्वव्यापी राम हुए। तुलसीदास ने चाहा कि रामकथा की भाषा अवध की मिट्टी की भाषा हो। क्या यह आश्चर्य नहीं कि एक आंचलिक बोली में रचे गये महाकाव्य ने विश्वभर के मानस में राम को बैठा दिया।

तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समय में थे, लेकिन तब भी वे अकबर से ज्यादा ऊपर थे। अपने समय के विख्यात पंडितों और धर्माचार्यों के विरोधों को झेलते हुए भी तुलसीदास जी चुपचाप अपना काम करते रहे,और लोकप्रिय हो गये। तुलसीदास ने कभी मंदिरों का विरोध नहीं किया, लेकिन वे राम को मंदिर से बाहर निकाल लाये। आज भी राम मंदिर में कम, लोक-मानस में ज्यादा बसते हैं, तो इसका श्रेय तुलसीदास को जाता है। यह एक आन्दोलन था, जिसका नेतृत्व अकेले तुलसीदास जी कर रहे थे। वे राम का चरित्र केवल अपने में नहीं, जन-जन के मन में भी बैठा देना चाहते थे। विश्व में तुलसीदास की कविता अकेली है, जिसने अपने कंधों पर यह दायित्व उठाया।

तुलसीदास हमें भ्रम में नहीं रखते। राम के अर्थ में प्रवेश कराते हुए वे सब दरवाजे खोल देते हैं। कोई किधर से भी आये, वह उसी राम के पास पहुँचेगा, जो उसका अपना है। तुलसीदास हमें अपने से बाँधते नहीं, राम को पाने के लिये खुला छोड़ते हैं। इसीलिये इतने वर्षों से रामचरितमानस का पारायण करने वाले, मानस पर अपनी-अपनी तरह से प्रवचन देने वाले, तुलसीदास के दोहों-चौपाइयों की व्याख्या करने वाले, रामलीला का मंचन करने वाले, रामायण जैसी अनेक फिल्में और धारावाहिक बनाने वाले राममय होकर अमर हो गये।

तुलसीदास चाहते, तो अपने नाम से कोई पंथ या सम्प्रदाय खड़ा कर सकते थे। लेकिन उनके पास न तो ऐसा विचार था, न अवकाश। वे अंत तक अपना धर्म निभाते चले गये। विनयपत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकीमंगल, पार्वतीमंगल सहित तुलसीदास जी की पूरी रचनावली में उनके समय की परिस्थितियाँ बोलती हैं। कई बार लगता है, तुलसीदास के दोहे-चौपाइयाँ हमारे दैहिक-दैविक और भौतिक संतापों को हर लेने के लिये ही तुलसीदास के हृदय में उतरीं। भोले-भाले और निर्मलचित्त वाले लोग च्दीनदयाल विरद सम्भारी। हरहुँ नाथ मम संकट भारीज्का सहारा लेकर संकटमुक्त होते देखे गये हैं।

तुलसीदास मर्यादा के कवि हैं। मर्यादापुरुषोत्तम राम की सर्वांगीण चेतना तुलसीदास के हरेक पद में घुली हुई महसूस होती है। समालोचकों ने तुलसीदास के साहित्य में कई बार कई तरह से खोजने की कोशिश की, कि ऐसा-वैसा कुछ मिल जाये, जो शास्त्र-विरुद्ध हो, काल-विरुद्ध हो, या समाज-विरुद्ध हो। एक-दो जगहें उन्होंने खोज भी लीं, लेकिन उससे न तो तुलसीदास को कोई नीचे उतार सका, न रामचरितमानस की महिमा भंग हुई। रामचरितमानस समुद्र की तरह गहन-गम्भीर है, अपनी मर्यादा में है। भारतीय काव्यशास्त्र के सूक्ष्म से सूक्ष्म नियम का मान रखने वाले तुलसीदास से श्रेष्ठ कोई नहीं। इसके बाद भी वे सबके आगे नतमस्तक होना जानते हैं।

रामचरितमानस करुणा का महाकाव्य है। आदि से अंत तक हमारे मन को पिघलाती रहती है रामकथा, बहुत रुलाती भी है। राम संसार भर के दुःखों को झेलते ही चले जाते हैं, और राम के दुःख हमारे लिये असह्य हो जाते हैं। यह है तुलसीदास का प्रताप। आदिकवि वाल्मीकि की रामायण में पूरे भारत का मन आ गया है, लेकिन यदि उस मन की व्याकुलता देखनी हो, मन का विषाद देखकर उससे उबरना भी हो, तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस से बड़ा कोई ठौर नहीं है।

तुलसीदास हमें हमारे अतीत में नहीं ले जाते, वर्तमान के सामाजिक विद्रूप का पूरा चित्र दिखाकर ऐसे भविष्य का स्वरूप सामने रखते हैं, जो रामराज्य की परिकल्पना के कुछ तो आसपास हो। तुलसीदास के रामचरितमानस को महाकाव्य के दायरे से बाहर निकालकर देखें तो पायेंगे कि वहाँ ऐसे भारतीय समाज का खाका है, जो आशा जगाता है। तब यह भी लगता है कि रामचरितमानस केवल नवाह्न पारायण और भक्तिपूर्वक गायन के लिये ही नहीं है, वह चरित्र में उतारने के साथ-साथ भविष्य निर्माण के लिये भी है। रामचरितमानस का शब्दार्थ भी हमें यही संकेत देता है।

मानस-मर्मज्ञों का मत है कि रामचरितमानस के श्रद्धापूर्वक अनुशीलन करने के बाद वेद-उपनिषद्-पुराण-स्मृतिग्रंथ और दूसरे ग्रंथों की शरण में जाने की आवश्यकता ही नहीं। उनका मानना है कि सब दर्शन ग्रंथों का सार लेकर ही रामचरितमानस की रचना हुई। मनु, याज्ञवल्क्य और आपस्तंब की स्मृतियों के जो निर्विवाद सूत्र हैं, उससे भी मानस की बुनावट हुई। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य से भी तुलसीदास ने प्रेरणा ली। अगस्त्य, अत्रि, भरद्वाज के आश्रमों के जो संदर्भ यहाँ हैं, वे वेदकालीन आश्रमों के विवरण भी देते हैं। जो नदियाँ, पर्वतमालाएँ और अरण्यावलियाँ हैं, उनमें भारत के भूगोल का रमणीय निसर्ग उभरकर आता है।

रामचरितमानस में जो धर्म स्थापित है, वह लोक कल्याण के लिये है। इसका एक भी दोहा या चौपाई हमें लोक-जीवन से दूर नहीं ले जाता, इसीलिये यह ग्रंथ लोक-पूजित है। जिस तरह हिन्दू धर्म को मानने वालों के घर-आंगन में तुलसी होती है, उसी तरह घर के भीतर तुलसीदास की रामचरितमानस ग्रंथ मौजूद रहता है। एक यही ग्रंथ है, जिसकी केवल पूजा नहीं होती, पाठ भी होता है। वेद,भागवत और गीता पढ़े नहीं जाते, पूजे जाते हैं। लेकिन कम पढ़े-लिखे भी तुलसीदास का रामचरितमानस बहुत चाव से पढ़ते देखे गये हैं। रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास घर-घर में हैं, और हमेशा रहेंगे।

तुलसी जयंती पर विशेष

रमेश रंजन त्रिपाठी

लेखक स्तंभकार हैं।

मानव समाज के पथप्रदर्शक तुलसी बाबा

हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल में सूरदास, कबीर, मीराबाई, रैदास, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम आदि अनेक संत कवि हुए जिन्होंने जन साधारण की भाषा में भगवद् भक्ति का संदेश दिया। सभी ने जन जागरण का प्रभावी आंदोलन चलाया। जन्म से दृष्टिहीन सूरदास ने भगवान श्रीकृष्ण के बाल्यकाल का अद्भुत चित्रण करते हुए वात्सल्य रस की वर्षा कराई तो मीराबाई ने अपने सखा गिरधर गोपाल के लिए घर-परिवार सबकुछ त्याग दिया। कबीर और जायसी ने निर्गुण ज्ञान की धारा बहाई। रैदास प्रेममार्ग पर चले।

चौदहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत से शुरू हुआ भक्ति आंदोलन उत्तर भारत तक पहुंचा और सत्रहवीं सदी तक चला। इस अवधि में अत्यधिक राजनीतिक अस्थिरता के चलते बार-बार सत्ता बदली। दिल्ली की सल्तनत में तुग़लक़, सैयद और लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर के आने के बाद मुगलों की हुकूमत स्थापित हुई। सत्ता के लिए संघर्ष और परिवर्तन हो रहा था। शासक और उनके सामंत निरंकुश हो रहे थे और जनता के सुख-दुख की बहुत परवाह नहीं करते थे। समाज और संस्कृति में भय तथा संशय पनप रहा था। धार्मिक आडंबर, कट्टरता, अंधविश्वास और नफरत बढ़ रही थी। तब त्रस्त लोगों के सहारा बने साधु, संत और कवि। उन्होंने साहित्य को माध्यम बनाकर सामाजिक सुधार, समानता, ईश्वर प्रेम और भक्ति का संदेश जन-जन तक पहुंचाया। भक्तिकाल के दौरान आध्यात्मिक क्षेत्र में रूढ़ियों की जंजीरें तोड़ने एवं कुरीतियों के निवारण में ज्ञान, प्रेम और भक्ति की विचारधारा ने सशक्त भूमिका निभाई। हताश मन को लक्ष्य पाने के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी। संतों, कवियों ने लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया, मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्तिभाव जागृत करते हुए निराशा में डूबे लोगों को मानसिक संबल दिया और धार्मिक तथा सामाजिक चेतना जागृत करने का महती कार्य प्रभावशाली तरीके से किया। इस कालखंड को भक्तिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे स्वर्णकाल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्णयुग और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक-जागरण काल कहा है।

हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल में सूरदास, कबीर, मीराबाई, रैदास, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम आदि अनेक संत कवि हुए जिन्होंने जन साधारण की भाषा में भगवद् भक्ति का संदेश दिया। सभी ने जन जागरण का प्रभावी आंदोलन चलाया। जन्म से दृष्टिहीन सूरदास ने भगवान श्रीकृष्ण के बाल्यकाल का अद्भुत चित्रण करते हुए वात्सल्य रस की वर्षा कराई तो मीराबाई ने अपने सखा गिरधर गोपाल के लिए घर-परिवार सबकुछ त्याग दिया। कबीर और जायसी ने निर्गुण ज्ञान की धारा बहाई। रैदास प्रेममार्ग पर चले। भक्तिकाल के अम्बर पर अनेक जगमगाते सितारों के बीच एक देदीप्यमान सूर्य का उदय हुआ, जिसे सभी गोस्वामी तुलसीदास के नाम से जानते हैं। सगुणोपासक भक्ति शाखा के निर्विवाद शीर्षस्थ संत कवि तुलसी बाबा ने समाज में नई सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक चेतना जगाने का क्रांतिकारी कार्य किया। जब जन-जागरण काल में अनेक संत शिरोमणि नव चेतना की अलख जगाने का कार्य कर रहे थे, तब तुलसीदास जी इतने विशेष क्यों हो गए? इसे समझने का प्रयास करते हैं।

गोस्वामी जी के समय भारतीय सनातन संस्कृति के अधिकांश ग्रंथ अभिजात्य वर्ग की भाषा संस्कृत में होते थे। संस्कृत का अपेक्षाकृत कम प्रचलन होने से जन साधारण को धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जानकारी के लिए वर्ग विशेष पर निर्भर रहना पड़ता था। उस समय के अनेक संतों की भाँति गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपनी बात समझाने के लिए जन-साधारण की भाषा का सहारा लिया। गोस्वामी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की कथा को महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत कर आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक संदेश देते हुए जीवन जीने की कला सिखाई। भक्तिकाल में दो महाकाव्य लिखे गए, मलिक मोहम्मद जायसी का 'पद्मावत' और तुलसी बाबा की 'श्रीराम चरित मानस'। सभी जानते हैं कि लोकप्रियता एवं आदरभाव किसके लिए अधिक है। भारतीय संस्कृति के आदर्श श्रीराम को नायक बनाकर गोस्वामी जी ने अद्भुत ग्रंथ की रचना की और निराश लोगों को विश्वास दिलाया कि अधर्म के विरुद्ध संघर्ष में ईश्वर उनके साथ हैं। तुलसी बाबा की विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक आदि रचनाएं भी लोकप्रिय हैं परन्तु 'मानस' को जो धार्मिक प्रतिष्ठा प्राप्त है वह बेमिसाल है। हज़ारों भारतीय परिवार में 'मानस' को पूजाघर में रखा जाता है तथा स्नान करने के पश्चात पवित्र भाव से अत्यन्त श्रद्धा पूर्वक उसका नियमित पाठ किया जाता है।

'मानस' में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कुशल मार्गदर्शन दिया गया है। उदाहरण के लिए, अयोध्या नरेश दशरथ घोषणा करते हैं कि अगले दिन श्रीराम को युवराज पद पर सुशोभित कर दिया जाएगा। परंतु मंथरा के भड़काने पर महारानी कैकेयी महाराज दशरथ से पूर्व में उन्हें दिए गए दो वरदानों के बदले अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य और श्रीराम को चौदह वर्षों का वनवास मांग लेतीं है। जिस दिन श्रीराम को राजा बनना था उस दिन उन्हें पत्नी और अनुज के साथ जंगल जाना पड़ा, फिर भी वे वैसे ही शांत बने रहते हैं जैसे राजपद पाने पर रहते। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में स्थितप्रज्ञ बने रहने का यह उत्तम उदाहरण है। गोस्वामी जी ने 'मानस' में 'कर्म प्रधान बिस्व रचि राखा, जो जस करइ सो तस फल चाखा' से जीवन में कर्म को सर्वोपरि निरूपित किया है। 'दैव दैव आलसी पुकारा' से आलस्य त्यागने और 'मातु पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिनहिं बिचार करिअ सुभ जानी' लिखकर बड़ों बुजुर्गों के सम्मान एवं उनकी आज्ञा मानने का संदेश दिया है। रामकथा के माध्यम से उन्होंने समझाया है कि पति-पत्नी, भाई-भाई, स्वामी-सेवक के रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। 'मानस' के जन-जन में रचे बसे होने का प्रमाण यह है कि अनपढ़ वर्ग से लेकर उच्च शिक्षित वर्ग तक सभी तुलसी बाबा के मुहावरों का अक्सर प्रयोग करते मिल जाते हैं। आपको भी याद होंगे- का बरखा जब कृषि सुखाने, कोउ नृप होय हमें का हानि, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंचि सम, खग जाने खग ही की भाषा, सबहिं नचावत राम गुसाईं, समय जात नहिं लागत बारा, पर उपदेस कुसल बहुतेरे, उघरे अंत न होइ निबाहूँ आदि।

तुलसीदास जी ने केवल लिखा ही नहीं अपितु स्वयं प्रवाचक बनकर रामकथा का प्रचार प्रसार किया। इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने रामलीला का मंचन शुरू किया ताकि दर्शक रामकथा के संदेश को रोचक ढंग से आत्मसात कर सकें। प्रवचन और रामलीला के आदि प्रवर्तक गोस्वामी जी हैं। ऐसे क्रांतिकारी कदम किसी अन्य संत ने नहीं उठाए। उनके 'हनुमान चालीसा' की असाधारण लोकप्रियता एवं स्वीकार्यता के पश्चात अन्य देवी देवताओं के चालीसा लिखे जाने की परंपरा शुरू हो गई। जन साधारण को 'श्रीराम चरित मानस' के जरिए अपनी भाषा में वेद, पुराण आदि समस्त ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त होने लगा। लोगों को मानव अवतार में परमपिता परमात्मा मिल गए। श्रीराम की सभी लीलाएँ मानवोचित हैं जो प्रत्येक श्रद्धालु के अंतर्मन को प्रभावित करती हैं। नाम स्मरण के रूप में भक्तों को भगवद् भक्ति का सुगम उपाय मिल गया। लोगों में विश्वास पैदा हुआ कि धर्म के मार्ग पर धैर्य पूर्वक चलते हुए कुशल रणनीति बनाकर रावण जैसे सर्वशक्तिमान अहंकारी राक्षस का भी अंत किया जा सकता है। और, इन सभी बातों से बढ़कर गोस्वामी जी की अपनी तपस्या के प्रभाव ने 'श्रीराम चरित मानस' को भक्ति साहित्य के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में स्थापित कर दिया जो सदियों से मानव समाज का मार्गदर्शन कर रहा है।

दृष्टिकोण

तनुजा चौबे

लेखक साहित्यकार हैं।

मुखौटे के पीछे का सच, खुशी का पीछे छूट जाना

जिंदगी को सहजता और सरलता से जीना ही जीवन का एकमात्र मूल मंत्र है। जब व्यक्ति भौतिक दुनिया से रूबरू होता है तो उसकी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक घटना है। यह आकर्षण व्यक्ति को बाहरी रूप से पूरी तरह बदल देता है। यह बदलाव बहुत तेजी से होता है, जबकि कोई भी स्थायी बदलाव बहुत धीरे-धीरे होता है। तेजी से हुआ बदलाव उतनी ही तेजी से बदलता भी रहता है और मन भी उसके साथ परिवर्तित होता रहता है। तब अंतर्मन और बाहरी बदलाव के बीच संघर्ष होने लगता है और व्यक्ति मुखौटा लगाकर जीवन जीने लगता है, जो उसे बहुत कठिन परिस्थिति में डाल देता है।

इसका उदाहरण अभी-अभी सोशल मीडिया पर तेजी से चलन में आई एक तस्वीरों की तकनीक से देखा जा सकता है, जिसमें किसी तस्वीर के चेहरे को लेकर तरह-तरह के सुसज्जित परिधानों और परिवेश में तस्वीर बना दी जाती है। पति-पत्नी की तस्वीर लेकर उसे बेहद सुंदर बगीचों या प्रेमिल आकृतियों में बदल दिया जाता है, जो एक आभासी संसार है। बहुत-सी स्त्रियां और लड़कियां उसमें अपनी तस्वीरें बनाकर खुश हो रही हैं।

आश्चर्य तो तब हुआ जब भारतीय परिधान पहनने वाली बहुत-सी स्त्रियां भी इस तरह दिखना चाहती हैं, जो शायद वास्तविक जीवन में किसी न किसी सुरक्षा, सामाजिक मर्यादा या अपनी परिस्थितियों के कारण संभव नहीं हो पाता। लेकिन उन तस्वीरों के माध्यम से वे अपनी दबी-छिपी ख्वाहिशों को बाहर ला रही हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु जब आप उन कपड़ों में सहज महसूस करती हैं तो उन्हें पहनने में भी कोई बुराई नहीं है। फिर खुद को ऐसे घेरे में रखकर क्यों जिएं, जिसमें आप खुश नहीं हैं?

वैसे ही, जो इस बदलाव को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। लेकिन वही एआई जब मनोरंजन या अपनी ख्वाहिशों के प्रतिरूप के रूप में सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है, तो यह आपकी दबी हुई इच्छाओं का ही प्रतिरूप है। फिर एआई का विरोध क्यों करना?

यही सारी बातें हैं जो व्यक्ति को स्वयं के भीतर परेशान कर देती हैं। जब आप खुलकर विरोध नहीं करते और दोहरे व्यवहार के साथ जीते हैं तो उससे मानसिक परेशानी भी होती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती। हर तरह से स्वयं को समय के अनुरूप बदलाव दिखाने वाले लोग वास्तव में बदलते हैं या केवल बदलने का ढोंग करते हैं, इसका प्रभाव जीवन पर निश्चित रूप से दिखाई देता है।

यह बीमारियों को आमंत्रित करने का रास्ता भी बन सकता है। कभी भी कथनी और करनी में अंतर होता है तो उसका सीधा नुकसान शरीर को होता है। कहा जाता है- ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है।

जब हम मुखौटा पहनकर जिंदगी जीते हैं तो अपने अहं पर एक आवरण रखकर उसकी लगातार सुरक्षा करते रहते हैं। इस आवरण को बनाए रखने के लिए भीतर निरंतर संघर्ष चलता रहता है। यही आंतरिक संघर्ष हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को लगातार तनाव की स्थिति में रख सकता है और हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बार-बार सक्रिय होने लगता है। इसके परिणामस्वरूप शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और धीरे-धीरे इसका प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगता है।

पति-पत्नी की ऐसी तस्वीरों और प्रेमिल आकृतियों को देखकर यह भी समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं वे ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन अपने अहं और वास्तविक रवैये के कारण कई बार उनके भीतर तनाव बना रहता है। दुनिया के सामने स्वयं को हमेशा खुश रखने और खुश दिखाने की प्रक्रिया में भी बहुत ऊर्जा खर्च होती है। बाहर से खुश दिखाई देने और भीतर की इच्छाओं को दबाकर रखने के बीच का यह अंतर व्यक्ति के भीतर निरंतर संघर्ष पैदा करता रहता है।

जब आप ऐसी दोहरी जिंदगी जीते हैं तो भीतर के संघर्ष में पड़ जाते हैं और अपने अहं को एक झूठे आवरण से ढक लेते हैं। उस आवरण को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। धीरे-धीरे इसका प्रभाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। इस आंतरिक संघर्ष के कारण आपका नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है, जिसका नतीजा यह होता है कि आप भावनात्मक रूप से बीमार होने लगते हैं।

इसी तरह अध्यात्म का ज्ञान देने वाले बहुत से लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़कर उनका ज्ञान जगह-जगह देने लगते हैं। यह किताबी ज्ञान तो होता है, लेकिन अंदर से वे काम, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष से भरे होते हैं। तब वे भी एक मुखौटे वाली जिंदगी जी रहे होते हैं।

कई लोग कार्यालय में अत्यंत विनम्र, सहयोगी और शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से वे लगातार क्रोध, असंतोष या दबाव में रहते हैं। नौकरी या सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपनी वास्तविक भावनाओं को दबाते रहते हैं। घर लौटने के बाद वही दबा हुआ तनाव चिड़चिड़ेपन या रिश्तों में दूरी के रूप में सामने आ सकता है। यानी बाहर एक व्यक्तित्व और भीतर दूसरा-यह भी आधुनिक जीवन का एक रूप है।

आज के समय में कई लोग अपनी वास्तविक आय और आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च करके जीवन जीने की कोशिश करते हैं। आय सीमित होने के बावजूद महंगी कार, घर का जरूरत से अधिक सामान और दूसरी भौतिक सुविधाएं जुटाने के लिए लोन और किस्तों का सहारा लिया जाता है। धीरे-धीरे घर सामान से भर जाता है, लेकिन मन भीतर से असंतोष और आर्थिक तनाव से भरने लगता है। दूसरों के सामने संपन्न और खुश दिखाई देने की कोशिश में व्यक्ति अपनी आर्थिक व्यवस्था तक बिगाड़ लेता है और एक ऐसी नकली जिंदगी जीने लगता है, जो उसके वास्तविक जीवन से मेल नहीं खाती।

आजकल बच्चों को विदेश भेजना भी एक तरह का स्टेटस सिंबल बन गया है। कई माता-पिता अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक कर्ज लेकर बच्चों को विदेश भेजते हैं और आर्थिक दबाव में अपनी सहज जिंदगी खो देते हैं। बच्चे भी दूर चले जाते हैं और परिवार साथ रहते हुए भी भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है। सवाल यह है कि इस दिखावे की कीमत पर हम अपनी जिंदगी के कितने अच्छे पल खो देते हैं?

मुखौटा लगाकर जीना कई बार अपनी ही खुशियों और इच्छाओं से समझौता करना होता है। दूसरों को खुश रखने की कोशिश में हम अपनी वास्तविक खुशी कहीं पीछे छोड़ देते हैं।

विश्व फोटोग्राफी दिवस पर विशेष

श्वेता गोयल
लेखक शिक्षक हैं।

187 वर्षों में क्रांतिकारी सफर

आज कैमरा लगभग हर हाथ में है। मोबाइल फोन ने फोटोग्राफी को स्टूडियो और पेशेवर कैमरों की सीमाओं से निकालकर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। कभी फोटो खिंचवाना एक विशेष अवसर हुआ करता था, जिसके लिए स्टूडियो जाना पड़ता था और तस्वीर मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। आज जन्मदिन से लेकर यात्रा, त्योहार, पारिवारिक समारोह, प्रकृति, भोजन, सड़क और यहां तक कि क्षणिक भावनाओं तक, सब कुछ कैमरे के फ्रेम में सुरक्षित हो रहा है। हालांकि कैमरा सबके पास होने का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति अच्छा फोटोग्राफर भी है। तकनीक तस्वीर बना सकती है लेकिन दृष्टि ही उसे अर्थ देती है। एक उत्कृष्ट तस्वीर के पीछे केवल महंगा कैमरा या अत्याधुनिक लेंस नहीं होता।

किसी दृश्य को स्थायी रूप से सुरक्षित कर लेना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता था। आज वही काम हमारी हथेली में रखा एक छोटा-सा स्मार्टफोन पलक झपकते कर देता है। एक क्लिक और सामने का दृश्य तस्वीर में बदल जाता है; दूसरा क्लिक और वही तस्वीर दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच जाती है। फोटोग्राफी ने इन 187 वर्षों में केवल तकनीक का सफर तय नहीं किया बल्कि मनुष्य की स्मृतियों, संवेदनाओं, कला, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक संवाद को देखने का नजरिया भी बदल दिया है। इसी अद्भुत यात्रा को याद करने का अवसर है 19 अगस्त का 'विश्व फोटोग्राफी दिवस'। आज कैमरा लगभग हर हाथ में है। मोबाइल फोन ने फोटोग्राफी को स्टूडियो और पेशेवर कैमरों की सीमाओं से निकालकर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। कभी फोटो खिंचवाना एक विशेष अवसर हुआ करता था, जिसके लिए स्टूडियो जाना पड़ता था और तस्वीर मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। आज जन्मदिन से लेकर यात्रा, त्योहार, पारिवारिक समारोह, प्रकृति, भोजन, सड़क और यहां तक कि क्षणिक भावनाओं तक, सब कुछ कैमरे के फ्रेम में सुरक्षित हो रहा है। हालांकि कैमरा सबके पास होने का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति अच्छा फोटोग्राफर भी है। तकनीक तस्वीर बना सकती है लेकिन दृष्टि ही उसे अर्थ देती है। एक उत्कृष्ट तस्वीर के पीछे केवल महंगा कैमरा या अत्याधुनिक लेंस नहीं होता। प्रकाश और छाया का संतुलन, फ्रेम की संरचना, विषय का चयन, कैमरे का कोण, पृष्ठभूमि, रंग, समय और सही क्षण की पहचान, ये सभी मिलकर एक तस्वीर को प्रभावशाली बनाते हैं। अनुभवी फोटोग्राफरों की दृष्टि में असली कौशल केवल यह तय करना नहीं है कि फ्रेम में क्या शामिल किया जाए बल्कि यह समझना भी है कि क्या बाहर छोड़ दिया जाए। यही चयन साधारण दृश्य को असाधारण बना देता है। किसी तस्वीर में तकनीकी पूर्णता महत्वपूर्ण है लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसमें धड़कता हुआ मानवीय भाव। मुस्कान, पीड़ा, संघर्ष, आशा, प्रेम, अकेलापन, उत्सव या करुणा, जब कोई तस्वीर इन भावनाओं को बिना शब्दों के दर्शक तक पहुंचा देती है, तभी वह सचमुच यादगार बनती है।

फोटोग्राफी का इतिहास भी उतना ही रोमांचक है, जितना उसका वर्तमान। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस में लुई डागुएरे की डागुएरियोटाइप प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया। फ्रांसीसी सरकार ने इस प्रक्रिया के अधिकार हासिल कर उसे व्यापक रूप से दुनिया के लिए उपलब्ध कराया और यही तारीख आगे चलकर विश्व फोटोग्राफी दिवस के प्रतीकात्मक आधार से जुड़ गई। डागुएरियोटाइप में चांदी की परत चढ़ी धातु की प्लेट पर अत्यंत सूक्ष्म छवि दर्ज होती थी। आज के तात्कालिक डिजिटल कैमरों की तुलना में यह प्रक्रिया बेहद धीमी और श्रमसाध्य थी, फिर भी उसने मानव सभ्यता को अपनी दुनिया को स्थायी छवि के रूप में दर्ज करने की अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की। फोटोग्राफी के विकास के साथ कैमरों का आकार छोटा होता गया, एक्सपोजर का समय घटता गया और तस्वीरों को सुरक्षित रखने के तरीके सरल होते गए। फिल्म कैमरों ने लंबे समय तक इस कला पर राज किया। श्वेत-श्याम तस्वीरों से रंगीन फोटोग्राफी तक का सफर अपने आप में तकनीकी क्रांति था। इसके बाद डिजिटल कैमरे आए और फिर स्मार्टफोन कैमरों ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कैमरा प्रणालियां प्रकाश की कमी सुधारती हैं, चेहरों की पहचान करती हैं, पृष्ठभूमि को अलग करती हैं, गतिशील दृश्यों को स्थिर करती हैं और कुछ ही क्षणों में ऐसी तस्वीरें तैयार कर देती हैं, जिनके लिए कभी विशेषज्ञ उपकरणों और वर्षों के अभ्यास की आवश्यकता होती थी।

फोटोग्राफी की इस यात्रा का सबसे दिलचस्प अध्याय 'सेल्फी' है। सेल्फी युवा संस्कृति, सोशल मीडिया और डिजिटल अभिव्यक्ति का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है लेकिन स्वयं की तस्वीर लेने का विचार स्मार्टफोन युग की देन नहीं है। सोचिए, 1839 में किसी व्यक्ति को अपनी तस्वीर लेने के लिए कैमरा तैयार करना, रोशनी तलाशना और कई मिनट तक बिना हिले खड़ा रहना पड़ता था लेकिन आज वही काम हम कुछ सैकेंड में कई बार कर सकते हैं। कॉर्नेलियस शायद यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनकी वह प्रयोगात्मक तस्वीर एक दिन सेल्फी संस्कृति की ऐतिहासिक शुरुआत के रूप में याद की जाएगी। उनकी वह छवि आज भी अमेरिकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के संग्रह में सुरक्षित है। फोटोग्राफी का महत्व केवल व्यक्तिगत स्मृतियों तक सीमित नहीं है। इतिहास के अनेक अध्याय तस्वीरों के बिना अधूरे होते। युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक आंदोलन, वैज्ञानिक उपलब्धियां, महान व्यक्तित्व, बदलते शहर और विलुप्त होती संस्कृतियां, इन सबका दृश्य दस्तावेज फोटोग्राफी ने तैयार किया है। विश्व फोटोग्राफी दिवस केवल कैमरे या तस्वीर का दिवस नहीं बल्कि देखने की कला का उत्सव है, उस दृष्टि का, जो सामान्य दृश्य में असाधारण अर्थ खोज लेती है। फोटोग्राफी हमें ठहरना सिखाती है, किसी क्षण को ध्यान से देखना सिखाती है और बीत चुके समय को स्मृति के रूप में फिर से हमारे सामने ला खड़ा करती है।

विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र करें पूर्ण : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य संस्थाओं में मानव संसाधन की उपलब्धता, निर्माणाधीन स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं, क्रिटिकल केयर सेवाओं, ई-एचएमआईएस पोर्टल और स्वास्थ्य संस्थाओं में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सकों की विभागीय स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री

श्री शुक्ल ने जिला अस्पतालों और क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक में कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के साथ वहां चिकित्सकों, विशेषज्ञों, नर्सिंग एवं अन्य आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए, ताकि नागरिकों को इन सेवाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।

ई-एचएमआईएस पोर्टल के सुदृढ़ीकरण की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आंकड़ों का सटीक, अद्यतन और समयबद्ध संधारण बेहतर योजना एवं मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक है। उन्होंने पोर्टल की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाने, आवश्यक तकनीकी सुधार करने तथा विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले डेटा को प्रभावी रूप से एकीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को इस प्रकार विकसित किया जाए कि विभागीय योजनाओं, स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थिति और सेवाओं की उपलब्धता की प्रभावी मॉनिटरिंग संभव हो।

निर्माणाधीन स्वास्थ्य संस्थाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश–उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्माणाधीन स्वास्थ्य संस्थाओं का कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और यदि किसी परियोजना में तकनीकी, प्रशासनिक अथवा अन्य कारणों से बाधा आ रही है तो उसका तत्काल निराकरण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं प्रारंभ करने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भवन के साथ-साथ फर्नीचर, आवश्यक उपकरण एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी समय पर सुनिश्चित की जाएं, ताकि स्वास्थ्य संस्थाओं को पूर्ण रूप से तैयार कर नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री सुखवीर सिंह, आयुक्त स्वास्थ्य श्री धनराजू एस. सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुरैना में खुदाई के दौरान निकले 1913 के सिक्के

जॉर्ज पंचम के नाम से जारी था एक रुपया, प्रशासन ने बरामदगी के निर्देश दिए

मुरैना (नप्र)। मुरैना में ग्रीन फील्ड हाईवे निर्माण के दौरान ग्राम डोंगर पुर लोधा के पास खुदाई में पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम करीब 5 बजे खुदाई के दौरान कुछ सिक्के ग्रामीणों को मिले। वहीं, एक जेसीबी संचालक को भी खुदाई के दौरान सिक्के मिलने की बात सामने आई है। सिक्के मिलने का वीडियो सामने आने के बाद मंगलवार को प्रशासन को मामले की जानकारी मिली।प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को सिक्के बरामद कर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सिक्कों पर जॉर्ज पंचम और 1913 अंकित– मिले सिक्कों पर 'जॉर्ज वी किंग इमप्रीरो' और वर्ष 1913 अंकित है। सिक्के के दूसरे हिस्से पर 'वन रुपया इंडिया' लिखा हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सिक्के ब्रिटिश काल के हैं। इनकी ऐतिहासिक स्थिति और अन्य जानकारी की पुष्टि संबंधित विभाग की जांच के बाद होगी।

11.6 ग्राम वजन, 91 प्रतिशत चांदी– पुरातत्व विभाग के जिला अधिकारी अशोक शर्मा के अनुसार, बरामद सिक्के का वजन करीब 11.6 ग्राम है। इसमें करीब 91 प्रतिशत चांदी होने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने बताया कि सिक्के पर 1913 और 'वन रुपया इंडिया' अंकित है। ग्रामीणों को कुल कितने सिक्के मिले हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। एक सिक्के का वजन 11.6 ग्राम और करीब 91 प्रतिशत चांदी की पुष्टि की है।

जेसीबी संचालक से भी जानकारी ली जा रही– खुदाई के दौरान एक जेसीबी संचालक को भी सिक्के मिलने की बात सामने आई है। प्रशासन अब यह पता कर रहा है कि खुदाई के दौरान कुल कितने सिक्के

मिले और वे किस स्थान से निकले। इस संबंध में थाना माता बसैया पुलिस से भी जानकारी ली जा रही है।

पुलिस को सिक्के कलेक्ट करने के निर्देश– एडीएम अश्वनी रावत ने बताया कि ग्रीन फील्ड हाईवे निर्माण के दौरान खुदाई में पुराने चांदी के सिक्के मिलने की जानकारी मिली है। पुलिस को मामले की जांच कर सिक्कों को कलेक्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।जांच पूरी होने के बाद बरामद सिक्कों को पुरातत्व विभाग के सुपुर्द किया जाएगा।

सिक्कों की संख्या और स्थान की जानकारी जुटा रहा प्रशासन– फिलहाल प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि खुदाई के दौरान कुल कितने सिक्के मिले हैं और ये किस स्थान से बरामद हुए हैं। पुलिस और पुरातत्व विभाग की जांच के बाद सिक्कों से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

जॉर्ज पंचम का 1 रुपये का चांदी का सिक्का के बारे में जानिए– ब्रिटिश भारत के दौर में जारी किया गया जॉर्ज पंचम का 1 रुपये का सिक्का ऐतिहासिक महत्व रखने वाला चांदी का सिक्का है। यह सिक्का जॉर्ज पंचम के शासनकाल में 1911 से 1936 के बीच जारी किया गया था। उस दौर में भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और सिक्कों पर तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट की तस्वीर और नाम अंकित किए जाते थे। जॉर्ज पंचम के 1 रुपये के सिक्के में करीब 91.7 प्रतिशत चांदी होती है। इसका वजन लगभग 11.66 ग्राम और व्यास करीब 30.5 मिलीमीटर होता है। इन सिक्कों की ढलाई बॉम्बे (मुंबई) और कलकत्ता (कोलकाता) टकसाल में की गई थी।

बच्चों की कल्पनाशीलता ने दिया प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश

हरा-भरा इंदौर का संकल्प लेकर किया गया पौधरोपण

इंदौर। शहर के गांधी हॉल में मंगलवार को नन्हें बच्चों ने पेंटिंग और फेंसी ड्रेस प्रतियोगिता के साथ स्लोगन लेखन के माध्यम से प्रकृति, पर्यावरण, जल और जंगल के संरक्षण का अभूतपूर्व संदेश दिया। नन्हें बालक-बालिकाओं की तूलिका ने रंगों का अद्भुत संसार रच दिया। यह आयोजन मां अहिल्या सेवा संस्था मध्यप्रदेश एवं श्रीजी नारी शक्ति एवं शिक्षा विकास समिति की ओर से प्रकृति सहेजो पर्यावरण बचाओ अभियान की थीम पर आयोजित किया गया था। मां अहिल्या सेवा संस्था मध्यप्रदेश की डायरेक्टर डॉ. आरती मेहरा ने बताया कि सावन और राखी और हरियाली महोत्सव के मद्देनजर गांधी हॉल में

विभिन्न उत्पादों के स्टाल अतिथियों और नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। मां अहिल्या सेवा संस्था की उपाध्यक्ष रश्मि बाकीवाला ने बताया कि यह प्रोग्राम मुख्य अतिथि शंकर लालवानी के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर महिलाओं और युवतियों ने विभिन्न व्यंजनों के स्टाल भी लगाए। अपरान्ह तीन बजे पेड़ लगाओ स्वच्छ सुंदर और स्वस्थ हरा भरा इंदौर बनाओ अभियान के तहत बच्चों से दो-दो पौधों का रोपण करवाया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों दो हाथ और दो पेड़ लगाने और उनका संरक्षण करने का और उन्हें पौधे से पेड़ बनाओ से अभियान से जोड़ना रहा। निशुल्क ड्राइंग, स्लोगन और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर अतिथियों ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी, विशेष अतिथि सीबी रॉकस्टार चिंतन बाकीवाला थे। मां अहिल्या सेवा संस्था की डायरेक्टर डॉ. आरती मेहरा, मां अहिल्या सेवा संस्था की उपाध्यक्ष रश्मि बाकीवाला और श्रीजी नारी शक्ति और विकास समिति की डायरेक्टर श्वेता विभोर जैन, सहसंयोजक एडवोकेट संजय मेहरा और विभोर जैन सहित बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे।

एसडीएम अपने क्षेत्र के निकायों की लीगेसी डंपसाइट एवं कचरा प्रसंस्करण केंद्रों का करें निरीक्षण: कलेक्टर

छतरपुर। कलेक्टर मृणाल मीना की अध्यक्षता में मंगलवार को नगर पालिका के कार्यों की समीक्षा बैठक जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी पीओ डूडा आयशा अंसारी सहित नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र के नगरीय निकायों की लीगेसी डंपसाइट एवं कचरा प्रसंस्करण केंद्रों का निरीक्षण करें। उन्होंने सीएमओ को नगरीय क्षेत्रों में बल्क वेस्ट जनरेटर को चिन्हित कर उनका पंजीयन कराने के निर्देश दिए। राजनगर निकाय में इस कार्य पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। साथ ही होटल संचालकों को अपने स्तर पर कचरा प्रसंस्करण के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

सड़कों पर आवारा पशु न आएं, निरंतर चलाएं अभियान, गौशालाओं की करें निगरानी– कलेक्टर ने छतरपुर शहर में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर नगर पालिका अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि गोवंश सड़कों पर न आएं।

राजघाट कॉलोनी दतिया में 13 सरकारी क्वार्टरों से हटाया गया अवैध कब्जा

दतिया। राजघाट कॉलोनी में लंबे समय से अनधिकृत कब्जे में बताए जा रहे सरकारी आवासों को खाली कराने के लिए प्रशासन ने मंगलवार को कार्रवाई की। एसडीएम कोर्ट के बेदखली आदेश के बाद तहसील, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और 13 सरकारी क्वार्टरों को कब्जे से मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की।

प्रशासन ने पहले संबंधित लोगों को आवास खाली करने के लिए नोटिस और निर्धारित समय दिया था। इसके बावजूद कई क्वार्टर खाली नहीं किए गए। कार्रवाई के दौरान कुछ कब्जाधारियों ने स्वयं आवास खाली कर दिए, जबकि कुछ स्थानों पर टीम ने अंदर रखा सामान बाहर निकलवाकर क्वार्टरों को कब्जामुक्त कराया।

कुछ आवासों पर ताले लगे मिले, जिन्हें प्रशासन ने खुलवाया।

मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस बल और नगर पालिका का अमला भी मौजूद रहा। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी आवास पात्र शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के उपयोग के लिए हैं, इसलिए इन पर अनधिकृत कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13 क्वार्टरों पर कार्रवाई– कार्रवाई के दौरान जिन 13 आवासों को चिन्हित किया गया, उनमें एनजी-14, एनजी-16, एनआई-29, जी-5, जी-24, जी-35, एच-28, आई-6, आई-22, एनआई-7, एनआई-27, एनआई-30 और एनआई-28 शामिल हैं। प्रशासनिक रिकॉर्ड में इन आवासों पर अलग-अलग व्यक्तियों का कब्जा दर्ज बताया गया है।

नर्मदा से प्राप्त शिवलिंग स्वयं सिद्ध माने जाते हैं विख्यात पंडित सोमेश परसाई ने कराया रूद्राभिषेक, उमड़े श्रद्धालु

सोहागपुर। श्रावण मास सावन का तीसरा सोमवार सोहागपुर नगर के लिए सौभाग्यशाली सिद्ध हुआ है। आयोजक समाजसेवी कन्नूलाल अग्रवाल, प्रदेश भाजपा व्यापारी संघ मीडिया प्रभारी गौरव अग्रवाल मोंटू अग्रवाल, गोलू अग्रवाल परिवार ने मंगल भवन में नर्मदापुरम निवासी विख्यात पंडित सोमेश परसाई के सानिध्य में शिवलिंग निर्माण एवं भव्य रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें 101 सपत्नीक जोड़ों ने भगवान् भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करके रूद्राभिषेक के आयोजन में शामिल हुए। इसी अवसर पर पूर्व विधायक एवं पूर्व वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ठाकुर,क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह आदि ने भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। इस अवसर पर धर्माचार्य सोमेश परसाई ने नर्मदेश्वर शिवलिंग की महिमा बताते हुए कहा कि मां नर्मदा के पत्थर से निर्मित शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। आपने कहा कि नर्मदा से प्राप्त शिवलिंग स्वयं सिद्ध माने जाते हैं। वहीं अन्य स्थानों से लाए गए पत्थर के शिवलिंग की

विधि-विधान से प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है। अपनी कथा को विस्तार देते हुए कहा कि भगवान शिव के अभिषेक में उपयोग होने वाले विभिन्न द्रव्यों की महिमा भी श्रद्धालुओं को कहा कि दही से अभिषेक करने से शीतलता, घी से वंश वृद्धि, शहद से रोगों के शमन और धन की प्राप्ति तथा शक्कर से ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं विशेष रूप से विद्यार्थियों को भगवान शिव का शक्कर से अभिषेक करने की बात कही। पंचामृत से अभिषेक का भी विशेष महत्व है। धन की कामना रखने वाले श्रद्धालु गन्ने के रस एवं नारियल के पानी से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। हालांकि इन सभी द्रव्यों से अधिक महत्व मां नर्मदा और मां गंगा के जल से भगवान शिव के अभिषेक अति उत्तम माना गया है। आपने अंत में कहा कि नर्मदा जल से भगवान शिव का अभिषेक एवं नर्मदेश्वर के दर्शन का विशेष धार्मिक महत्व धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है।

भस्म आरती एवं भजनों से मंत्रमुग्ध हुए श्रोता – सोहागपुर में विख्यात पंडित सोमेश परसाई के द्वारा नगर में पहली बार रूद्राभिषेक कराया गया है।यह सोभाय अग्रवाल परिवार के खाते में गया।कार्यक्रम में नगर के श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तथा भस्म आरती का आनंद लिया। वहीं संगीत कलाकारों ने भगवान शिव एवं अन्य देवी-देवताओं से जुड़े धार्मिक भजनों की उत्कृष्ट प्रस्तुतियां दी गईं। इसके उपरांत

प्रसादी वितरण की गई। जिसमें नगर ही नहीं आस-पास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजक वरिष्ठ समाजसेवी कन्नूलाल अग्रवाल ने कार्यक्रम में सहभागी सभी श्रद्धालुओं एवं धर्मावलंबियों का आभार व्यक्त किया है ।

संक्षिप्त समाचार

बाल विवाह रोकने की ग्रामीणों ने ली शपथ

पीपल्या रसोड़ा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आंगनवाड़ी केंद्रों में ध्वजारोहण के साथ बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यकर्ताओं हेमलता, उमा भदौरिया, किरण शर्मा, रुक्मणि वर्मा, कोसर बी तथा सहायिकाओं आशा कार्यकर्ता रेखा नायक, धनकुंवर लववंशी और रेखा प्रजापति ने लोगों को बाल विवाह नहीं करने और न ही परिवार या आसपास ऐसा विवाह होने देने की शपथ दिलाई। ग्रामीणों ने बाल विवाह की जानकारी मिलने पर पंचायत एवं संबंधित अधिकारियों को सूचना देने तथा बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए आवाज उठाने का संकल्प लिया। इस दौरान बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण में सामूहिक भूमिका निभाने की अपील की गई।

डेढ़ लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बैजनाथ धाम पहुंचे

राजगढ़। राजगढ़ सावन के तीसरे सोमवार को नरसिंहगढ़ स्थित बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर में डेढ़ लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे। इस दौरान 20 से ज्यादा कांवड़ यात्राएं भी बाबा बैजनाथ धाम पहुंचीं। सोमवार सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। दोपहर तक मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भारी भीड़ रही। 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। रविवार को करीब 10 हजार श्रद्धालुओं ने बाबा बैजनाथ के दर्शन किए थे। सोमवार को यह संख्या कई गुना बढ़ गई। कांवड़ यात्राओं में शामिल श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए थे। नरसिंहगढ़ मेले से लेकर बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर तक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। पुलिस जवानों ने भीड़ और यातायात व्यवस्था संभाली। व्यवस्थाओं का जायजा लेने एसडीएम अजय प्रताप पटेल, तहसीलदार अनरिका कजोटिया, नायब तहसीलदार सुनीता और थाना प्रभारी गूंजा सोलंकी मौके पर मौजूद रहे। राजगढ़ जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था। नगरपालिका टीम, पुलिस प्रशासन, शांति समिति, पटवारी दल और एनसीसी टीम ने भी व्यवस्थाओं में सहयोग किया। अधिकारियों ने मंदिर और मेला क्षेत्र का लगातार निरीक्षण किया। सावन के तीसरे सोमवार को बाबा बैजनाथ धाम में दिनभर भक्तों की भीड़ रही। मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयकारों से गूंजता रहा।

पचोर में नशामुक्ति के खिलाफ रैली :स्कूली बच्चे, संस्थाएं शामिल; नुक्कड़ नाटक से दिया नशामुक्ति संदेश

सारंगपुर। पचोर में मंगलवार को नशे के खिलाफ एक विशाल नशामुक्ति रैली का आयोजन किया गया। लायंस क्लब पचोर के नेतृत्व में सुबह 11 बजे पुराने बस स्टैंड से शुरू हुई इस रैली में शहर की लगभग दर्जनभर सामाजिक संस्थाओं के सदस्य और निजी स्कूलों के छात्र-छात्राएं शामिल हुए। प्रतिभागियों ने हाथों में नशामुक्ति का संदेश देती तख्तियां लेकर शहर के प्रमुख मार्गों पर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। रैली के दौरान 'जन-जन ने ठाना है, नशे को मिटाना है', 'नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो' और 'नशा मुक्त हो देश हमारा, यही है संकल्प हमारा' जैसे नारों से शहर गूंज उठा। विद्यार्थियों ने राहगीरों और दुकानदारों से नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार व आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करने की अपील की। यह रैली पुराने बस स्टैंड से शुरू होकर सराफा बाजार, नगर पालिका, गांधी चौक, मंडी, नया बस स्टैंड और थाना परिसर होते हुए वापस पुराने बस स्टैंड पर समाप्त हुई। इस दौरान प्रमुख चौराहों पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया, जिनके माध्यम से शराब, तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। नाटकों के जरिए युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। रैली के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को नशामुक्त समाज बनाने की शपथ दिलाई गई। लोगों ने संकल्प लिया कि वे स्वयं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहेंगे और दूसरों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इस कार्यक्रम में लायंस क्लब अध्यक्ष डॉ. इंसाफ अंसारी, महिला विंग उड़ान की अध्यक्ष डॉ. रेणु विजयवर्गीय, राजगढ़ से डॉ. धर्मेंद्र भदौरिया, नपा अध्यक्ष विकास करोड़िया, मंडल अध्यक्ष विकास दीक्षित, पूर्व लायन अध्यक्ष दिलीप सोनी, दीपक जुलानिया सहित ब्रह्माकुमारी बहनों और गायत्री परिवार के सदस्यों ने सहभागिता की। वक्ताओं ने जोर दिया कि नशे के खिलाफ केवल अभियान चलाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिवार और समाज को मिलकर युवाओं को जागरूक करना होगा।

पटवारी, सचिव एवं जीआरएस की सार्थक ऐप पर ई-अटेंडेंस अनिवार्य कलेक्टर ने सुठालिया में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान की तैयारियों एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा की

राजगढ़ । मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के आगामी आयोजन की तैयारियों को लेकर सुठालिया में कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बैठक में अभियान की तैयारियों के साथ पूर्व में प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने सार्थक अटेंडेंस की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी पटवारी, पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस) सार्थक ऐप के माध्यम से अनिवार्य रूप से ई-अटेंडेंस दर्ज करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। सार्थक अटेंडेंस में खराब प्रदर्शन पाए जाने पर जल संसाधन विभाग को पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

लंबित शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर कार्रवाई : कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने संबल, जननी सुरक्षा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं बाल आशीर्वाद योजना से संबंधित लंबित शिकायतों की समीक्षा कर उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में खराब प्रदर्शन पर पशु चिकित्सा विभाग में शिकायतों का कार्य देखने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर की 7 दिवस की वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। वहीं, टीएल बैठक में अनुपस्थित रहने पर कोषालय अधिकारी एवं उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ब्यावरा द्वारा शिकायतों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ब्यावरा को अगली टीएल बैठक में स्वयं उपस्थित होकर स्थिति प्रस्तुत करने तथा 7 दिवस में लंबित शिकायतों की प्रगति रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग : कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना की गहन समीक्षा करने के निर्देश दिए तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को योजना की प्रगति एवं लंबित प्रकरणों की व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

अमरगढ़ में खराब प्रदर्शन पर रीडर को निलंबित करने के निर्देश : अमरगढ़ में खराब प्रदर्शन पर कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने रीडर को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही पीठासीन अधिकारी को भी बदलने के निर्देश दिए गए, ताकि प्रकरणों के निराकरण में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित हो सके।

राजस्व शिकायतों के निराकरण में सख्ती के निर्देश : कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने निर्देशित किया कि नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन से संबंधित शिकायतों के निराकरण में राजस्व अधिकारी पूरी तरह सजग एवं गंभीर रहें। लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

आधार पेंडेंसी के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण : कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने आधार से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए इन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए।

उद्यम क्रांति योजना के ऋण से स्थापित उद्यमों की होगी समीक्षा : कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत वितरित ऋणों की समीक्षा करते हुए आगामी टीएल बैठक में यह जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए कि ऋण प्राप्त हितग्राहियों द्वारा उद्यम स्थापित किया गया है अथवा नहीं। जिन हितग्राहियों द्वारा उद्यम स्थापित नहीं किया गया है, उनकी विभागवार रिपोर्ट आगामी टीएल बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एनालॉग पनीर की जब्ती का एक भी प्रकरण दर्ज नहीं होना गंभीर विषय है। इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई नहीं किए जाने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। संत रविदास जयंती की कलश यात्रा के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश संत रविदास जयंती के अवसर पर प्रस्तावित कलश यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को सुव्यवस्थित कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध रूप से आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। पेट्रोल पंपों की शिकायतों पर सख्त निगरानी पेट्रोल पंपों से संबंधित शिकायतों, विशेषकर ईंधन में पानी की मिलावट के मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने संबंधित समिति को सख्ती से निगरानी करने तथा शिकायत मिलने पर नियमानुसार जांच एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छात्रावास, आंगनवाड़ी एवं विद्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक में छात्रावास, आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय सहित अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को इन संस्थानों से संबंधित समस्याओं एवं आवश्यकताओं का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासन की सेवाओं को नागरिकों तक सुगमता से पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सभी विभागीय अधिकारी लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा करते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें।

सड़क पर गिरने को तैयार पोल, हादसे का इंतजार

राजगढ़। शहर की मुख्य सड़क पर गांधी चौक में बिजली का एक पोल हादसे को न्योता दे रहा है। पोल नीचे से सड़ चुका है और लगातार सड़क की ओर झुकता जा रहा है। इसी पोल पर 11 केवी की घरेलू लाइन और स्ट्रीट लाइन के केबल लगे हैं। ऊपर तारों का भारी जाल और उनका खिंचाव पोल पर दबाव बढ़ा रहा है। ऐसे में कभी भी पोल सड़क पर गिर सकता है। बावजूद इसके बिजली कंपनी इसे बदलने के बजाय हादसे का इंतजार करती नजर आ रही है। पोल गिरने की स्थिति में आसपास के 100 से अधिक परिवारों की बिजली आपूर्ति प्रभावित होने के साथ सड़क से गुजरने वाले लोगों की जान पर भी खतरा पैदा हो सकता है। रहवासी कई बार बिजली कंपनी कार्यालय में शिकायत कर चुके हैं। जनसुनवाई के माध्यम से प्रशासन को भी समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन हर बार कार्रवाई का आश्वासन ही मिला। समय बीतने के साथ पोल का झुकाव बढ़ता जा रहा है और खतरा भी लगातार गंभीर होता जा रहा है। रहवासी राजेश सोनी, पिंटू विजयवर्गीय, नवीन शर्मा, राम शर्मा, मुकेश आदि ने बताया कि पोल बदलने की मांग के बावजूद बिजली कंपनी ध्यान नहीं दे रही है। उनका कहना है कि किसी बड़े हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय कंपनी को पहले ही खतरा दूर करना चाहिए। रहवासियों ने प्रशासन से तत्काल पोल बदलवाने के निर्देश देने की मांग की है। इधर... मकान की छत से सटकर खड़ा है दूसरा पोल गांधी चौक से कुछ दूरी पर भंडारा गली में हनुमान मंदिर के सामने भी बिजली पोल की स्थिति चिंताजनक है। दिलीप सिंह पंवार के मकान के पास लगा पुराना लोहे का पोल झुककर मकान से टिक गया था। शिकायत के बाद पिछले साल कंपनी ने पुराने पोल के नीचे हल्का सपोर्ट लगाकर उसे सीधा किया और पास में नया पोल खड़ा कर दिया। लेकिन नया पोल भी कुछ ही दिन बाद झुक गया। रहवासियों के अनुसार बेहद कम गहराई में लगाया गया और फिलिंग में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। अब यह पोल मकान से टिका हुआ है। बारिश में गीली दीवारों पर करंट फैलने की आशंका रहती है। इसकी शिकायत भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन स्थिति जस की तस है। दोनों पोल के संबंध में बिजली कंपनी के एई से चर्चा करने के लिए कई बार संपर्क के बाद कॉल रिसीव नहीं किया।

खिलचीपुर में सावन के तीसरे-सोमवार निकली बाबा महाकाल की सवारी

राजगढ़। राजगढ़ के खिलचीपुर में सावन के तीसरे सोमवार की रात बाबा महाकाल की भव्य सवारी निकाली गई। फूलों से सजी पालकी में विराजे बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु सड़कों पर उमड़ पड़े। ढोल, मंजीरों और डमरू की थाप के बीच निकली सवारी में भक्त लगातार हर-हर महादेव और बाबा महाकाल के जयकारे लगाते नजर आए। उज्जैन की तर्ज पर आयोजित इस सवारी से पूरा नगर भक्तिमय हो गया।

फूलों से सजी पालकी में विराजे बाबा महाकाल : महाकाल सेवा समिति की ओर से देशप्रेमी गली स्थित पंचमुखी शिव मंदिर में बाबा महाकाल को फूलों से सजी पालकी में विराजमान किया गया। विधिवत पूजा-अर्चना के बाद शिवभक्त पालकी लेकर नगर भ्रमण के लिए रवाना हुए। सवारी के आगे और पीछे ढोल, मंजीरे और डमरू वादक चल रहे थे। भक्तों के जयकारों और धार्मिक धुनों से नगर की गलियां गूंज उठीं।

दर्शन के लिए मार्ग पर पहले से जुटे श्रद्धालु : बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु सवारी मार्ग पर पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सवारी इमली स्टैंड पहुंची, वहां मौजूद भक्तों ने पूजा-अर्चना कर बाबा का स्वागत किया। इसके बाद सवारी पटवा बाजार, पिपली बाजार, सराफा बाजार और सुभाष चौक से होते हुए आगे बढ़ी। रास्ते में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल की आरती उतारी और पालकी पर पुष्प अर्पित किए।

ढोल-डमरू और जयकारों से गूंजा नगर : सवारी के दौरान नगर की गलियों में भक्ति गीतों के साथ ढोल-मंजीरों और डमरू की धुन सुनाई देती रही। शिवभक्त बाबा महाकाल के जयकारे लगाते हुए सवारी के साथ चलते रहे। पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। कई स्थानों पर भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा-अर्चना की।

रात 10 बजे पंचमुखी शिव मंदिर पहुंची सवारी : सावन के तीसरे सोमवार की रात निकली बाबा महाकाल की सवारी नगर भ्रमण के बाद करीब रात 10 बजे पंचमुखी शिव मंदिर पहुंची। यहां सवारी का समापन किया गया। महाकाल सेवा समिति के सदस्यों और शिवभक्तों की सक्रिय भागीदारी से आयोजित इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सवारी के दौरान पूरे खिलचीपुर में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला।

कृषि विस्तार अधिकारियों की हड़ताल शुरू

राजगढ़। ई-एचआरएमएस प्रणाली में जियो-फेंसिंग के जरिए उपस्थिति दर्ज कराने के विरोध सहित तीन सूत्रीय मांगों को लेकर जिले के कृषि विस्तार अधिकारियों ने सोमवार से हड़ताल शुरू कर दी। सोमवार से जिले भर के कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय परिसर में ही धरने पर बैठ गए यहीं वे 20 अगस्त तक पूरे कार्यालय समय में प्रदर्शन करेंगे। मध्यप्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ के आह्वान पर जिले के अधिकारी 17 से 20 अगस्त तक कार्यालयीन कामकाज से दूर रहकर प्रदर्शन करेंगे। कृषि विस्तार अधिकारियों के हड़ताल पर जाने से शासन द्वारा इस वर्ष घोषित किसान कल्याण वर्ष के तहत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ने की संभावना है। इसके अलावा किसानों को फसलों से संबंधित तकनीकी जानकारी देने, खेतों में मार्गदर्शन करने और खाद वितरण व्यवस्था में भी परेशानी आ सकती है। कृषि विभाग में फील्ड स्तर पर किसानों से सीधे जुड़े काम मुख्य रूप से इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से संचालित होते हैं। परिसर में चरणबद्ध आंदोलन के तहत धरने पर बैठे कृषि विस्तार अधिकारी।

कलेक्टर श्री वानखड़े ने जन सुनवाई के दौरान सुनी 130 से अधिक आवेदकों की समस्याएं

दतिया ,निप्र। दतिया विधानसभा उप निर्वाचन सम्पन्न होने के पश्चात् आज मंगलवार से जन सुनवाई पुनः प्रारंभ हो गई है। न्यू कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखड़े द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से आए 130 से अधिक आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निराकरण के लिए निर्देशित किया। अनिराकृत आवेदनों के लिये समय-सीमा निर्धारित कर अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान ग्राम पीपरी तहसील इन्दरगढ़ निवासी मानवेन्द्र पाल पुत्र श्री जगराम पाल नारायण प्रदूदयाल, राधे, सुरेश, मुन्ना ने आवेदन दिया कि प्रार्थीगण ने अपनी आरजी का वर्ष 2019 में सहमति अनुसार बटवारा करवाया था। जस पर पटवारी ऑफलाईन अक्शा में बटवारा आदेश का पालन नहीं किया गया था और न ही उस पर लाईन अंकित की गई जिसके कारण प्रार्थीगणों को काफी तरह की जमीनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र सुनवाई करते हुए तहसीलदार इन्दरगढ़ को नियमानुसार नियत समय में कार्यवाही कर निराकरण करने के निर्देश दिए। ग्राम अतरेंटा तहसील सेवढ़ा निवासी दिलीप कुशवाहा पुत्र श्री विजय सिंह कुशवाह ने ग्राम अतरेंटा के सर्वे नम्बर 299 से अतिक्रमण हटाने का आवेदन दिया।

राजगढ़ में ई-अटेंडेंस के विरोध में कृषि विभाग के कर्मचारी

चार दिन की कलमबंद हड़ताल पर, एसडीएम को दिया ज्ञापन

राजगढ़। राजगढ़ में कृषि विभाग के कर्मचारियों ने ई-एचआरएमएस प्रणाली में ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता के विरोध में सोमवार से कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। कृषि विस्तार अधिकारियों ने उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से काम का बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने ई-अटेंडेंस को अव्यावहारिक बताते हुए अपनी अन्य मांगों के निराकरण की मांग की और एसडीएम राजगढ़ को ज्ञापन सौंपा। यह आंदोलन 17 से 20 अगस्त तक चलेगा।

17 से 20 अगस्त तक चलेगा कार्य बहिष्कार : मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ की जिला इकाई के आह्वान पर जिलेभर के कृषि विस्तार अधिकारी चार दिन तक कलमबंद कार्य बहिष्कार करेंगे। कर्मचारियों का आंदोलन 17 से 20 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग परिसर में चलेगा। इस दौरान कर्मचारी ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

ई-अटेंडेंस को बताया अव्यावहारिक : संघ ने ज्ञापन में बताया कि ई-एचआरएमएस प्रणाली में ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता को समाप्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनका काम मुख्य रूप से मैदानी और भ्रमण आधारित है, ऐसे में ई-अटेंडेंस की व्यवस्था उनके लिए व्यावहारिक नहीं है।

शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा आंदोलन : कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने कहा कि आंदोलन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। कर्मचारियों ने प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि हड़ताल के दौरान अनुशासन बनाए रखा जाएगा और प्रशासन की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। संघ की प्रमुख मांगों में ई-एचआरएमएस में ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त करना शामिल है। इसके साथ ही कृषि विस्तार अधिकारियों के लिए 2500 रुपए का डीडीपी-पे लाभ देने की मांग की गई है। अतिरिक्त केंद्र का दायित्व संभालने वाले अधिकारियों को वर्तमान 900 रुपए के बजाय 7 हजार रुपए प्रतिमाह भत्ता देने की मांग भी रखी गई है। जिले में ई-अटेंडेंस प्रणाली के विरोध का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले शिक्षक सहित अन्य कर्मचारी संगठन भी ई-अटेंडेंस को अव्यावहारिक बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। अब कृषि विभाग के कर्मचारियों ने भी कार्यालय के बाहर बैठकर इसी व्यवस्था के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन के दौरान कृषि विस्तार अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम राजगढ़ को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने शासन और प्रशासन से मांगों पर जल्द निर्णय लेकर ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त करने और अन्य मांगों का भी निराकरण करने की अपील की है।

आंदोलन के दौरान जिला अध्यक्ष दीपक वर्मा, जिला महामंत्री सचिन परमार, जिला उपाध्यक्ष राकेश परमार, आकांक्षा गुप्ते, शिल्ला करोड़, लितिका तिवारी, लक्ष्मण तिवारी, योगेश त्यागी, अजयपाल परमार, विशाल नागर, संदीप नागर और अरविंद मेवाड़ा सहित कई कृषि विस्तार अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

संत रविदास की जयंती पर भोपाल में समरसता संकल्प सम्मेलन

सीएम बोले- जातिवाद के चुनौती भरे माहौल में सामाजिक समरसता लाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी

भोपाल (नप्र)। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार को राजधानी भोपाल के रवीन्द्र भवन में 'संत रविदास सामाजिक समरसता संकल्प सम्मेलन' आयोजित किया गया। सम्मेलन से पहले बरखेड़ा स्थित प्राचीन संत रविदास मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें संतों का रथ, बैंड-बाजे, ढोल, बग्गी, ऊंट-घोड़े और महिला मंडल के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई रवीन्द्र भवन पहुंची। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में कलश शिरोधार्य किया।

सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, विधायक प्रदीप लारिया सहित संत समाज और संत रविदास के अनुयायी मौजूद रहे।

जातिवाद के चुनौती भरे माहौल में समरसता लानी है- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज के दौर में जातिवाद के चुनौती भरे माहौल के बीच समाज में समरसता लाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का जीवन और उनके विचार पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोने का मार्ग दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में सामाजिक समरसता के अभियान को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी (उत्तर प्रदेश) स्थित संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से पवित्र मिट्टी और पावन जल लेकर आई यह समरसता संकल्प कलश यात्रा समाज में समानता और भाईचारे का नया संदेश देगी।

गांव-गांव लेकर जाएंगे कलश यात्रा

SC विभाग के मंत्री नागर सिंह चौहान ने सम्मेलन में अभियान की रूपरेखा बताते हुए कहा कि यह कलश यात्रा महत्वपूर्ण है। इसे गांव-गांव तक ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संत रविदास के संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा- कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन संत रविदास जी के त्याग बलिदान को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है।

सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों का चक्काजाम

ब्यूटीशियन ने सड़क पर मेकअप कर विरोध जताया व्यापारियों ने आत्मदाह की चेतावनी दी

भोपाल (नप्र)। भोपाल में कमर्शियल गतिविधियों पर कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को व्यापारियों ने रोशनपुरा चौराहे पर चक्काजाम कर दिया। करीब पौने दो घंटे चले प्रदर्शन में बड़ी संख्या में व्यापारी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते रहे। महिलाएं भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुईं।

व्यापारियों ने कहा कि रहवासी इलाकों में वर्षों से कारोबार संचालित हो रहे हैं, ऐसे में अचानक सीलिंग की कार्रवाई से दुकानदारों के साथ कर्मचारी और उन पर निर्भर परिवार भी प्रभावित होंगे। व्यापारियों ने सरकार से भोपाल का मास्टर प्लान जल्द लागू करने, मिक्स्ड लैंड यूज का प्रावधान करने और गुजरात की तर्ज पर अनधिकृत विकास नियमितीकरण कानून-2022 लागू करने की मांग की। उग्र आंदोलन की चेतावनी देने के बाद व्यापारियों ने धरना समाप्त कर दिया। उधर, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भोपाल के व्यापारियों के साथ अभी बैठक करेंगे और उनकी बात सुनेंगे।

सड़क पर बैठकर नारेबाजी, जन-गण-मन भी गाया

रैली के दौरान कई जगह व्यापारी सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सामूहिक रूप से जन-गण-मन गाकर भी विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है कि वे सरकार को टैक्स दे रहे हैं और वर्षों से इन क्षेत्रों में कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में अचानक दुकानें बंद कराने के बजाय सरकार को व्यावहारिक समाधान निकालना चाहिए।

टैक्सी हड़ताल से यात्री परेशान

रेलवे स्टेशन पर कैब नहीं मिली, ऑटो चालक मांग रहे डेढ़ से दो गुना किराया

भोपाल (नप्र)। एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ टैक्सी चालक संघ की हड़ताल के चलते भोपाल में मंगलवार रात 12 बजे से ओला, उबर समेत अन्य कैब का संचालन बंद है। बुधवार सुबह भोपाल रेलवे स्टेशन पर इसका सीधा असर दिखाई दिया। यात्रियों ने ऑनलाइन कैब बुक करने की कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ियां उपलब्ध नहीं हुईं। मजबूरन उन्हें ऑटो और दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ा। जिसका फायदा ऑटो चालकों ने उठाया। उन्होंने डेढ़ से दो गुना किराया वसूल किया।

स्टेशन पर बाहर से पहुंचे यात्रियों को सामान के साथ काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। कुछ यात्रियों ने आरोप लगाया कि कैब नहीं मिलने का फायदा उठाकर ऑटो चालक भी डेढ़ से दो गुना किराया मांग रहे हैं।

स्टेशन पर मिलीं यात्री आकांक्षा ने बताया कि वह करीब आधे घंटे से कैब का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके घुटने में परेशानी है और साथ में दो बेटियां हैं, जिनमें एक दो साल और दूसरी आठ साल की है। उन्हें रोहित नगर स्थित अपोलो अस्पताल जाना है, लेकिन कैब नहीं मिल रही।

यात्री सत्यम ने बताया कि वह उत्तराखंड के रहने वाले हैं और कर्नाटक से भोपाल पहुंचे हैं। उन्हें सुल्तानिया अस्पताल जाना है। काफी देर तक कैब बुक करने की कोशिश के बावजूद वाहन नहीं मिला।

ऑटो ही बना सहारा

कैब सेवा बंद होने के कारण स्टेशन पर यात्रियों के सामने ऑटो ही प्रमुख विकल्प रह गया। यात्रियों का कहना है कि सामान्य दिनों में ऑनलाइन कैब आसानी से मिल जाती थी, लेकिन हड़ताल के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। कुछ यात्रियों ने ऑटो चालकों पर अधिक किराया वसूलने का आरोप भी लगाया।

स्टेशन पर कैब रोककर भुगतान नहीं करने दे रहे संगठन के लोग

हड़ताल के बीच भोपाल स्टेशन पर बुकिंग लेकर यात्रियों को छोड़ने पहुंच रही कैब को लगातार रोका जा रहा है। संगठन से जुड़े लोग कैब चालकों को हड़ताल के दौरान वाहन नहीं चलाने की समझाइश दे रहे हैं और यात्रियों से कैब का भुगतान नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। अवधपुरी से कैब से भोपाल स्टेशन पहुंचे परिहार ने बताया कि उनकी कैब को भी स्टेशन पर रोक लिया गया। उनका कहना है कि उन्हें कैब का भुगतान करने नहीं दिया गया और वे बिना किराया दिए ही स्टेशन से उतर गए। उनका कहना था कि उन्होंने कैब बुक की थी और किराया देने के लिए तैयार थे, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने भुगतान नहीं करने दिया।

अवैध संबंधों के सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते

जबलपुर (नप्र)। दिल्ली निवासी एक युवक की शादी छतरपुर की युवती से हुई थी। पति ने पत्नी पर कई पुरुषों से अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था। इसी आधार पर उसने पत्नी के कथित संबंधों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, सीडी और उनके ट्रांसक्रिप्ट छतरपुर फैमिली कोर्ट में पेश किए थे। पति का कहना था कि ऐसी परिस्थितियों में वह पत्नी के साथ नहीं रह सकता। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने इन साक्ष्यों पर पर्याप्त विचार किए बिना पत्नी को हर महीने 6 हजार रुपए भरण-पोषण देने का आदेश दिया था।

पति के सबूतों पर दोबारा विचार करने के आदेश- पति ने फैमिली कोर्ट के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सोमवार को जस्टिस डीडी बंसल की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पति ने पत्नी के कई पुरुषों के साथ अवैध संबंध होने का दावा करते हुए साक्ष्य पेश किए हैं। ऐसे में भरण-पोषण के अधिकार पर फैसला लेने से पहले इन साक्ष्यों की जांच जरूरी है। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि फैमिली कोर्ट ने पति की ओर से पेश इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, सीडी और उनके ट्रांसक्रिप्ट पर पर्याप्त गंभीरता से विचार नहीं किया।